

✳Website : www.kalamlok.com✳

वर्ष - 10 अंक - 176

बक्सर, मंगलवार 27 अक्टूबर 2026

पृष्ठ - 8

मूल्य 2 रू.

कलम लोक

◄ 7 |

"निरभिमानी धन्य है; क्योंकि उन्हीं के हृदय में ईश्वर का निवास होता है।

एसआईआर के तीनों फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा

ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग का पक्ष, फॉर्म-6 और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर भी दी सफाई



नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने कहा कि यह याचिका केवल एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई है और इसमें कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। आयोग के मुताबिक, हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित जारी किए गए तीनों आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित हुए थे। आयोग ने कहा कि फाइलों पर चुनाव आयुक्तों की ओर से लिखे गए नोट, सुझाव या सवालों को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। फाइलें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे और अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं। आपात स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी लेने के बाद उसे फाइल पर दर्ज किया जाता है। आयोग ने चेतावनी दी कि अधिकारों से बाहर जाकर आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 पर आयोग ने कहा कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार, फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जबकि एसआईआर का घोषणा-पत्र अलग दस्तावेज है। आयोग ने माना कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को देखकर फॉर्म-6 में बदलाव होने का भ्रम पैदा हो सकता था। इसलिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया, ताकि यह भौतिक आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप हो सके।

आयोग ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में आने की जरूरत नहीं है।

बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। अपवाद की स्थिति में ही सुनवाई होगी और वह भी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ईसीआईनेट प्रणाली में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के लिखित आदेश के बिना किसी मतदाता का नाम न जोड़ा जा सकता है और न हटाया जा सकता है। आंकड़ों के अनुपालन की जांच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई है।

गोवा के 97 मतदाताओं और पश्चिम बंगाल के मामलों पर जवाब

गोवा के 97 कथित छूटे हुए मतदाताओं के मामले में आयोग ने बताया कि 88 लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा चुका है, छह लोग विदेश में हैं और तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों की ओर से दाखिल अपीलों पर आयोग ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में थीं और केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने नहीं लाई गई थीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया का दिया हवाला

याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया लागू होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित है। इसके तहत संसद में महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोग ने इसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया। आयोग ने यह भी कहा कि उसने अपनी कोई आंतरिक फाइल या गोपनीय टिप्पणी मीडिया को जारी नहीं की है।

विस्तृत जवाब दाखिल करने की मांगी अनुमति

चुनाव आयोग ने बताया कि दशहरा की छुट्टियों के कारण फिलहाल संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मामले के सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब देने की अनुमति मांगी है। आयोग के जवाब में एसआईआर के फैसलों, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर अपना पक्ष रखा गया है। अब मामले में आगे की सुनवाई और आयोग के विस्तृत जवाब पर नजर रहेगी।



सीजेपी में पड़ गई फूट? रांका और दास मुक्का मार रहे

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके विरोधियों के निशाने पर आए हुए हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलनों में खुद पीछे रहकर उन्होंने दोनों सह संयोजकों सौरभ दास और आशुतोष रांका को आग में धकेल दिया, जिससे उन्हें सात दिनों तक तिहाड़ में बंद रहना पड़ा है। कुछ लोग तो उनके उस बयान पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें दीपके ने लोगों से दिवाली तक आंदोलन रोकने की अपील की थी और उसी वीडियो संदेश में ये बात कही थी कि असल में सौरभ दास और आशुतोष रांका ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

अभिजीत दीपके ने नई तस्वीर पोस्ट कर बताई पूरी बात

सोशल मीडिया यूजर्स और विरोधियों ने दीपके के इस बयान को आंदोलनों से पल्ला झाड़ने और दास और रांका को मामले में फंसाने की चाल के रूप में देखा। अब इस बात की भी अटकलें लगाई जी रहीं हैं कि टीम के तीन कॉकरोचों यानी अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच फूट पड़ गई है। कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रही और दीपके ने उन दोनों के जेल से आने से पहले ही आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया।

इन्हीं आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने सोमवार (26 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों साथियों (खुद दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका) के साथ एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें तीनों ही नटखट और मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दीपके ने तंज कसते हुए लिखा है कि हमारे बीच 'अंदरूनी फूट' पड़ गई है। इस तस्वीर में तीनों नेताओं ने एकजुटता जाहिर करने के लिए एक ही तरह की यानी काली टी-शर्ट पहन रखी है और तीनों ही अजीब सा पोज दे रहे हैं। दीपके फोटो के बीच में हैं और सेल्फी ले रहे हैं, जबकि रांका और दास उन पर मुक्का मारते हुए पोज़ दे रहे हैं।

बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (स्थरू) ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया था। तब दोनों ने हलफनामा दिया था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया था। दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने दोनों को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। ऐसी भी चर्चा है कि ये तीनों नेताओं ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर चुप्पी साध ली है।

राजनाथ सिंह का खड़गे को जवाब

प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी टिप्पणियों से विचलित नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के ऊपर की गई टिप्पणी से आहत हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी टिप्पणियों से न तो विचलित किया जा सकता है और न ही जनसेवा के उनके संकल्प को कमजोर किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रविवार को पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई टिप्पणी से मैं स्तब्ध हूं। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह टिप्पणी कांग्रेस के किसी सामान्य कार्यकर्ता या किसी युवा नेता ने नहीं, बल्कि अपने को देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कहने वाली पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने आचरण से करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने बताया कि पर कांग्रेस के लोग यहीं नहीं रुके। अब कांग्रेस पार्टी खड़गे के शब्दों को जस्टिफाई कर फिर से लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी गलती स्वीकार कर खेद व्यक्त करने के बजाय कांग्रेस इस बयान को सही ठहराने में जुटी है। राजनाथ सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, खड़गे जिस पद पर आसीन हैं, उनसे सार्वजनिक जीवन में अधिक गंभीरता, संयम, मर्यादा और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है।



पैसे और धमकियों से डराया जा रहा है: ममता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर पैसे और धमकी के बल पर लोगों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ज्यादती काफी बढ़ गई है। आयोग ने उनसे सभी दस्तावेज जमा करने को कहा है, जबकि जिलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारियों, थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से लोगों को धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को कानूनी दस्तावेज, स्टांप पेपर और नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र उपलब्ध करा रही है, जबकि उनकी पार्टी के लिए सब कुछ रोक दिया गया है। यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आने वाले लोगों को भी उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

बेटियों की सुरक्षा का भरोसा देख पीएम मोदी बोले- योगी जी को थैंक्यू बोलो

वाराणसी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अरविंद गारमेंट्स कंपनी की नई इकाई का उद्घाटन करने के बाद वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान एक महिला कर्मचारी ने बेटियों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर अपने गांव में बदलती सोच का अनुभव साझा किया। महिला ने बताया कि अब परिवार अपनी बेटियों को नौकरी के लिए घर से बाहर भेजने को लेकर पहले की तुलना में अधिक सहज हो रहे हैं।



महिला कर्मचारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि कंपनी खुलने से उन्हें रोजगार का अवसर मिला है। इसके साथ ही गांव के परिवारों की सोच में भी बदलाव आने लगा है। पहले माता-पिता बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन अब सुरक्षित कार्यस्थल का भरोसा बढ़ने से वे उन्हें नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे हैं। महिला ने कहा कि कंपनी में काम करने के दौरान उन्हें सुरक्षित माहौल मिल रहा है। इसका असर आसपास के परिवारों पर भी दिखाई देने लगा है। अब लोग यह सोचने लगे हैं कि उनकी बेटियों को भी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।

महिला की बात सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराए और बीच में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, 'तो योगी जी को थैंक्यू बोलो।' उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री की बात सुनकर महिला कर्मचारी मुस्कुराईं और तुरंत जवाब दिया, 'थैंक्यू सर, सबको थैंक्यू सर।' महिला और प्रधानमंत्री के बीच हुई इस छोटी-सी बातचीत के दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। इस सहज संवाद में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू सामने आया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अरविंद गारमेंट्स कंपनी की नई इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने वहां कार्यरत महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। इसी दौरान महिला कर्मचारी ने बताया कि नई इकाई के खुलने से स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से महिलाओं को अपने आसपास ही काम करने का अवसर मिल रहा है। इससे उन्हें आजीविका का साधन मिलने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। महिला कर्मचारी के अनुसार, रोजगार के अवसरों के साथ सुरक्षित माहौल का भरोसा भी परिवारों की सोच बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पिंक बूथ जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों की सुनवाई को आसान बनाना है।

बेटियों को बाहर भेजने में अब कम हो रही झिझक

महिला कर्मचारी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि पहले परिवार बेटियों को घर से बाहर भेजने को लेकर अधिक चिंतित रहते थे। उन्हें इस बात की आशंका होती थी कि बाहर काम करने के दौरान उनकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं। अब जब महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो परिवारों का भरोसा भी बढ़ रहा है। महिला की बात से यह स्पष्ट हुआ कि केवल नौकरी मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार की सहमति और कार्यस्थल पर सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। जब माता-पिता को अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर विश्वास होता है, तो वे उन्हें रोजगार के लिए बाहर भेजने का निर्णय अधिक सहजता से ले पाते हैं।

गुवाहाटी के होटल में गोलीबारी, छह लोगों की मौत

गुवाहाटी (एजेंसी)। गुवाहाटी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां के होटल बिलास इन में गोलीबारी की घटना में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं, कई लोग घायल भी हुए हैं। यह होटल गुवाहाटी के लच्छित नगर में है। घटना सोमवार रात नौ बजे के करीब हुई। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ने इन मौतों की पुष्टि की है। गोलीबारी बोरा सर्विस के पास हुई। हादसे की जानकारी होते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। हमलावरों की पहचान के बारे में अभी तक जानकारी हासिल नहीं हो सकी है।

पुलिस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। हमलावरों की पहचान के बारे में अभी तक जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग में कई लोग, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, घायल हुए हैं।

एलपीजी वितरकों का प्रदर्शन

मांगें पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी के सीबीडी ग्राउंड में सोमवार को एलपीजी वितरकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 4,000 से अधिक वितरक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कमीशन में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में नए एलपीजी कनेक्शन बहाल करने और लंबे समय से लंबित परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा के साथ धनोटिया केके, गुरपाल मान, आशुतोष गर्ग, पीयूष और श्वेता सहित विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष और एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि वितरक वर्ष 2018 से कमीशन में व्यापक संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस अवधि में एलपीजी की कीमतों और परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन वितरकों के कमीशन में उसके अनुरूप बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कमीशन व्यवस्था वितरकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के अनुरूप नहीं है। बीएस शर्मा ने कहा, 2018 के बाद घरेलू एलपीजी की कीमत लगभग 450 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, कमर्शियल एलपीजी की कीमत 1,100 रुपये से बढ़कर 3,033 रुपये हो गई है। इसके बावजूद हमारे कमीशन में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई है।



प्रधानमंत्री मोदी ने डियर फ्रेंड लूला को ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर दी बधाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को बधाई दी है। पीएम ने उन्होंने अपना डियर फ्रेंड बताते हुए उम्मीद जताई की दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ की उन्नति के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र, राष्ट्रपति लूला को शानदार पुनर्निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। मैं भारत-ब्राजील की बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा तथा व्यापक बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को तत्पर हूं। उन्होंने आगे कहा, हम साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे, ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे, और एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत तथा टिकाऊ दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।

व्यापारियों ने रामलीला मैदान में कांग्रेस की 1 नवंबर की रैली दिवाली बाद करने की मांग दोहराई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के व्यापारियों ने रामलीला मैदान में एक नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की रैली को स्थगित करने की मांग दोहराई है। उन्होंने निर्णय पर विचार करने के संबंध में दिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का स्वागत किया। साथ ही, व्यापारियों ने कहा कि हमारा निवेदन है कि व्यापार के हित में रैली को दिवाली के बाद आयोजित किया जाए। व्यापारियों को दिवाली के त्योहार से पहले कांग्रेस की रैली के कारण भारी नुकसान की आशंका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बयान दिया कि वे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा करके ही कोई अंतिम निर्णय लेंगे।

इस संबंध में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से दिल्ली के व्यापारियों में आशा की किरण जगी है। हम उनके इस संवेदनशील रवैये का दिल से स्वागत करते हैं। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, व्यापारी संगठन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि आपकी अगली मीटिंग में आप दिवाली के पीक सीजन को देखते हुए दिल्ली के लाखों व्यापारियों की रोजी-रोटी का ख्याल रखते हुए रैली को दिवाली के बाद करने का अंतिम निर्णय लेंगे। व्यापारियों का कहना है कि इस साल धनतेरस 6 नवंबर (शुक्रवार) को है। धनतेरस को लेकर ही दिल्ली में सभी सेक्टरों में लगभग 25 हजार करोड़ का कारोबार होता है। इसके बाद 8 नवंबर को दीपावली और 10-11 नवंबर को भैया दूज तक ये पीक सीजन रहता है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 20 बड़े-बड़े होलसेल और रिटेल बाजार हैं, जिनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, दरियागंज, कमला मार्केट, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, नया बाजार, आजाद मार्केट, दरीबा ज्वैलरी मार्केट, किनारी बाजार, नबी करीम, करोल बाग, झंडेवालान और जामा मस्जिद शामिल हैं।

अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी बरी

सुल्तानपुर (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई।



यह मामला वर्ष 2018 में अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए अदालत में शुरू हुई।

मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन दलील दी थी कि यह बयान सद्भावना के तहत दिया गया था और इसके पीछे किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

नीतीश कुमार से टकराकर राजनीतिक वनवास झेलेंगे अनंत सिंह? जॉर्ज फर्नांडिस से शरद यादव तक के उदाहरणों ने बढ़ाई चुनौती



पटना (संवाददाता)। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ संबंधों का किसी नेता के राजनीतिक भविष्य पर कितना असर पड़ता है, यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। जेडीयू से जुड़े रहे कई दिग्गज नेताओं ने अलग राह चुनने के बाद अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ उनमें से कई का प्रभाव कमजोर पड़ गया। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के राजनीतिक सफर को इसी संदर्भ में देखा जाता है। अब अनंत सिंह के सामने भी ऐसा ही सवाल खड़ा है कि क्या वे नीतीश कुमार और जेडीयू से अलग होने के बाद अपनी राजनीतिक ताकत बरकरार रख पाएंगे या उन्हें भी राज्य की राजनीति में सीमित भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह की पहचान केवल किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में नहीं रही है। उनका व्यक्तिगत प्रभाव, समर्थकों के साथ संबंध और क्षेत्र में उनकी पकड़ उनकी राजनीति के प्रमुख आधार माने जाते हैं। यही वजह है कि जेडीयू से उनके अलगाव को दूसरे नेताओं के राजनीतिक अनुभवों के साथ रखकर देखने के बावजूद उनका मामला पूरी तरह एक जैसा नहीं माना जा सकता। एक ओर उनके सामने पार्टी के संगठन और राज्यव्यापी राजनीतिक समर्थन की चुनौती है, तो दूसरी ओर मोकामा में उनकी व्यक्तिगत पहचान उन्हें अलग राजनीतिक आधार प्रदान करती है।

जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। वे जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और पार्टी के शुरुआती राजनीतिक सफर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन समय के साथ नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेद बढ़े और पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई।

वर्ष 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जेडीयू से अलग राह अपनाई। इसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम और लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद किसी नेता के लिए अपने पुराने संगठन से अलग होकर चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। जॉर्ज फर्नांडिस के राजनीतिक प्रभाव में गिरावट के पीछे उनके नीतीश कुमार से मतभेदों के साथ-साथ गिरते स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण कारण माना गया। उनका उदाहरण उन नेताओं में शामिल किया जाता है, जिनकी पार्टी के भीतर कभी मजबूत स्थिति थी, लेकिन समय और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव ने उनके प्रभाव को सीमित कर दिया।

शरद यादव का नाम भी जेडीयू की राजनीति और नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वे जेडीयू के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अलग पहचान थी। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले का उन्होंने विरोध किया। इसके बाद दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद और गहरे हो गए। शरद यादव ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनते हुए लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने समर्थकों को एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के रूप में एकजुट रखने की थी। उनके पास ऐसा मजबूत स्वतंत्र जनाधार और कार्यकर्ता तंत्र नहीं था, जिसके सहारे वे अलग पार्टी को व्यापक स्तर पर स्थापित कर पाते। आगे चलकर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक सहारा लेना पड़ा। उनके अनुभव से यह बात सामने आती है कि किसी बड़े दल में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पद पर रहने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बावजूद स्वतंत्र राजनीतिक संगठन खड़ा करना अलग चुनौती है। अनंत सिंह के मामले में यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके सामने भी यह तय करने का सवाल है कि वे अपनी राजनीति को केवल मोकामा तक सीमित रखेंगे या उससे बाहर भी विस्तार देने की कोशिश करेंगे। शरद यादव का अनुभव बताता है कि राजनीतिक पहचान को संगठनात्मक ताकत में बदलना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा होती है।

आरसीपी सिंह का राजनीतिक सफर भी जेडीयू से अलग होने के बाद राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने की चुनौती को समझने का एक उदाहरण है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (ट्रूस) से राजनीति में आए आरसीपी सिंह ने जेडीयू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उनकी राजनीतिक ताकत का बड़ा हिस्सा जेडीयू के संगठन और सत्ता में उनकी भूमिका से जुड़ा था। नीतीश कुमार से दूरी बढ़ने और जेडीयू से अलग होने के बाद उन्हें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी 'आप सबकी आवाज' का विलय जन सुराज में कर दिया। उनके राजनीतिक सफर से यह सवाल उठता है कि क्या संगठन के भीतर मिला प्रभाव अपने आप में स्वतंत्र जनाधार का प्रमाण होता है। किसी पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर रहना और चुनावी क्षेत्र में अपने नाम पर समर्थकों को लामबंद कर पाना दो अलग-अलग बातें हैं।

अनंत सिंह के सामने भी इसी तरह की चुनौती आ सकती है, यदि वे मोकामा से बाहर अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसी एक विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभाव होना और पूरे राज्य में राजनीतिक संगठन खड़ा करना अलग-अलग स्तर की क्षमताओं की मांग करता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई और बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माध्यम से अपनी राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ाईं। उनके राजनीतिक सफर में गठबंधन और दलों के बीच बदलते समीकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद कुशवाहा के सामने अपने समर्थक वर्ग को एकजुट रखने की चुनौती बनी रही। उनकी राजनीति को कुर्मी-कोइरी यानी लव-कुश सामाजिक समीकरण के संदर्भ में भी देखा जाता रहा है। लेकिन इस सामाजिक आधार को स्थायी और स्वतंत्र चुनावी ताकत में बदलना उनके लिए आसान नहीं रहा। उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए समय-समय पर गठबंधन और रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा। यह उदाहरण बताता है कि किसी सामाजिक समूह के बीच पहचान होना और उस समूह के मतदाताओं का लगातार किसी एक नेता के पक्ष में मतदान करना अलग बातें हैं।

अनंत सिंह के सामने भी यह सवाल है कि उनका व्यक्तिगत समर्थन कितना स्थायी है और पार्टी से अलग होने के बाद वह किस हद तक चुनावी सफलता में बदल सकता है। यदि उनके समर्थक केवल मोकामा तक सीमित रहते हैं, तो उनका प्रभाव क्षेत्रीय बना रह सकता है। लेकिन यदि वे व्यापक राजनीतिक विस्तार चाहते हैं, तो उन्हें संगठन, कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन जुटाने की चुनौती का सामना करना होगा।

अनंत सिंह का राजनीतिक मॉडल उन नेताओं से अलग माना जाता है, जिनकी पहचान मुख्य रूप से पार्टी के संगठन, प्रशासनिक पद या राज्यस्तरीय सामाजिक समीकरणों से बनी थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान लंबे समय से चर्चा में रही है। उनके समर्थकों का एक वर्ग उन्हें किसी पार्टी के चुनाव चिह्न से अधिक उनके अपने नाम और स्थानीय प्रभाव के आधार पर देखता है। अनंत सिंह वर्ष 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करते रहे हैं। इन चुनावी सफलताओं को उनके क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। लगातार चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड इस धारणा को मजबूती देता है कि मोकामा में उनकी राजनीतिक ताकत केवल किसी एक दल पर निर्भर नहीं रही है। वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक सफर का खास उदाहरण माना जाता है। उस समय जेडीयू से अलग होने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। जेल में रहने के बावजूद वे चुनावी मैदान में उतरे और जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार को पराजित किया। इस परिणाम ने मोकामा में उनकी व्यक्तिगत चुनावी ताकत को चर्चा में ला दिया था। मोकामा क्षेत्र में भूमिहार समुदाय की उल्लेखनीय मौजूदगी और अनंत सिंह के समर्थकों के साथ उनके लंबे राजनीतिक संबंधों को भी उनकी स्थानीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि, किसी भी चुनाव में जीत केवल एक सामाजिक समूह या व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर तय नहीं होती। उम्मीदवार, राजनीतिक परिस्थितियां, चुनावी गठबंधन और मतदाताओं का रुख भी परिणाम को प्रभावित करते हैं।

अनंत सिंह के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि मोकामा में उनकी व्यक्तिगत पकड़ को क्या बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाया जा सकता है। किसी एक विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव जीतना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन राज्य की राजनीति में व्यापक भूमिका निभाने के लिए अधिक बड़े संगठन और विभिन्न क्षेत्रों में समर्थकों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जैसे दलों के पास अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनावी नेटवर्क का व्यापक ढांचा है। इन दलों के सामने किसी स्वतंत्र नेता के लिए पूरे राज्य में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता। स्वतंत्र उम्मीदवार या क्षेत्रीय नेता को अपने संसाधनों, समर्थकों और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर राजनीतिक मुकाबला करना पड़ता है। यदि अनंत सिंह मोकामा तक सीमित रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ चुनावी राजनीति जारी रखते हैं, तो उनका स्थानीय जनाधार उनके लिए महत्वपूर्ण बना रह सकता है। लेकिन यदि वे अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर राज्यव्यापी राजनीतिक विकल्प तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल अपने क्षेत्र के समर्थकों पर निर्भर रहने से आगे बढ़ना होगा। उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नेतृत्व तैयार करने, संगठन खड़ा करने और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समर्थन हासिल करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस लिहाज से उनकी आगे की रणनीति यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि वे स्थानीय प्रभाव वाले नेता बने रहते हैं या राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं।

बिहार में स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ व्यापक स्तर पर प्रभाव बनाए रखने की कठिनाइयों को समझने के लिए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का उदाहरण भी सामने आता है। पप्पू यादव ने अपनी अलग पार्टी के माध्यम से राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी को अपेक्षित स्तर पर स्थापित करने की चुनौती बनी रही। बाद में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ।

इस उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि किसी नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता और स्वतंत्र पार्टी की चुनावी सफलता हमेशा एक जैसी नहीं होती। पार्टी को टिकाऊ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, नेतृत्व की दूसरी पंक्ति, संसाधन और विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी समर्थन जुटाने की क्षमता जरूरी होती है। अनंत सिंह के लिए भी यही सवाल अहम है। मोकामा में उनका प्रभाव उनकी राजनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरे बिहार में अपनी अलग राजनीतिक पहचान को स्थायी रूप देने के लिए उन्हें व्यापक संगठनात्मक आधार की आवश्यकता हो सकती है।

नीतीश कुमार से अलग हुए नेताओं के अनुभवों को देखते हुए अनंत सिंह के सामने दो संभावित राजनीतिक रास्तों की चर्चा होती है। पहला, वे अपनी राजनीति को मोकामा और आसपास के क्षेत्र तक सीमित रखते हुए व्यक्तिगत जनाधार के दम पर आगे बढ़ें। दूसरा, वे अपनी स्वतंत्र पहचान को राज्यव्यापी राजनीतिक संगठन में बदलने का प्रयास करें। पहले रास्ते में उनका स्थानीय प्रभाव और समर्थकों के साथ संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरे रास्ते में उन्हें जेडीयू, भाजपा और महागठबंधन जैसे स्थापित राजनीतिक गठबंधनों के संगठनात्मक ढांचे का सामना करना होगा। राज्यव्यापी विस्तार के लिए केवल एक क्षेत्र में मजबूत पकड़ होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

नीतीश कुमार से दूरी के बाद कमजोर पड़ते गए कई दिग्गज नेता

बिहार की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा चर्चा में रही है कि नीतीश कुमार से राजनीतिक टकराव या जेडीयू से अलग होने के बाद किसी नेता के लिए अपनी पुरानी ताकत बनाए रखना आसान नहीं होता। हालांकि, हर नेता की परिस्थितियां अलग रही हैं, लेकिन कई पुराने राजनीतिक चेहरों के अनुभव इस सवाल को लगातार प्रासंगिक बनाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक, ऐसे कई नेता रहे जिन्होंने जेडीयू के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें कुछ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, तो कुछ ने संगठन और सरकार में प्रभावशाली पदों पर काम किया। इसके बावजूद पार्टी से अलग होने के बाद उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व और जनाधार को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन नेताओं के अनुभवों से यह सवाल उठता है कि किसी नेता की राजनीतिक ताकत का वास्तविक आधार क्या होता है। क्या संगठन के भीतर मिला पद और पार्टी का समर्थन ही चुनावी सफलता की गारंटी है, या किसी क्षेत्र में व्यक्तिगत लोकप्रियता और समर्थकों का मजबूत समूह भी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रख सकता है? अनंत सिंह का मामला इसी बहस के केंद्र में है।

विधायकी पर संकट ने बढ़ाई राजनीतिक अनिश्चितता

अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी चर्चा के बीच उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी सवाल उठे हैं। खबर में उल्लिखित घटनाक्रम के अनुसार, जेडीयू की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश किए जाने के बाद उनकी विधायकी पर संकट की स्थिति बनी हुई है। इस मामले का परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विधानसभा सदस्यता को लेकर किसी भी निर्णय का असर उनकी मौजूदा राजनीतिक भूमिका और आगे की रणनीति पर पड़ सकता है। हालांकि, सदस्यता के संबंध में अंतिम स्थिति सक्षम प्राधिकारी के निर्णय और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। उनके परिवार से जुड़ी राजनीतिक परिस्थितियां भी चर्चा में हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी से संबंधित सरकारी आवास खाली करने के नोटिस और 20 सूत्री समिति से जुड़े पद को लेकर सामने आई खबरों ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया है। इन घटनाक्रमों का व्यापक राजनीतिक अर्थ क्या होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो सकता है।

15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या

मुंह में ठूंस दिया कपड़ा, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर ली जान

नवादा (संवाददाता)। बिहार के नवादा में एक 15 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गयी जिले के नरहट थाना क्षेत्र के अबगिल गांव स्थित हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में पुलिस ने शव बरामद किया तो सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अबगिल गांव निवासी सुनील यादव की पुत्री नीतू कुमारी के रूप में की गई है। दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी। मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस बीच पुलिस ने तीन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना से मृतका के परिवार में मातम छा गया है।

बताया जाता है कि नीतू रविवार की शाम घर से शौच के लिए बाहर गई थी। काफी समय बाद भी वह नहीं लौटी, तब परिजनों को चिंता हुई। काफी तलाशने के बाद उसका शव गांव के हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर बधार में मृत अवस्था में बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि अपराधियों ने मृतका के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी है।

हत्यारों ने नीतू की आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बधार में शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर, हत्या की सूचना मिलते ही नरहट थानाध्यक्ष गौतम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

वारदात की जानकारी होने पर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारणों और अन्य बिंदुओं का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल, इस जघन्य हत्याकांड के बाद से अबगिल गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है। पुलिस ने आश्वसन दिया है कि जल्द की हत्याकांड का रहस्य सुलझा लिया जाएगा।

डेढ़ हजार साल पुरानी प्रतिमा चोरी मामले मे सीएम को लिखा पत्र

मधुबनी (संवाददाता)। अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के देवहार गांव स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से दुर्लभ प्रतिमाएं और पुरावशेष गायब होने का मामला सामने आया है. मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ के अवकाश प्राप्त सहायक संग्रहालयाध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है.

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में शिव कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि जिले के विभिन्न मंदिरों से प्रतिमाओं की चोरी के मामलों में प्रशासन की भूमिका की जांच होनी चाहिए. उनके अनुसार, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से विष्णु और महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमाएं तथा विष्णु प्रतिमा की पादपीठ गायब है.

अनंत सिंह पर कार्रवाई संजय झा का अधिकार क्षेत्र, जेडीयू के ऐक्शन से ललन सिंह ने पल्ला झाड़ा



पटना (संवाददाता)। बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी की रणनीति के खिलाफ अभियान चलाने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जदयू ने कार्रवाई तेज कर दिया है। पहले उन्हें पत्नी नीलम देवी समेत पार्टी से निकाला गया, फिर विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र सौंपा गया और अब वर्षों पुराने सरकारी आवास से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच अनंत सिंह पर कार्रवाई के सवाल से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होने कहा है कि यह संजय झा का अधिकार क्षेत्र है।

दिल्ली में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एक साथ दिखे। इसी दौरान कई मीडियाकर्मी उनके पास पहुंच गए। पत्रकारों ने अनंत सिंह पर जदयू की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल पूछा। सवाल सुनने के बाद ललन सिंह और संजय झा आगे बढ़ गए। पत्रकार भी उनके साथ हो गए। गाड़ी में बैठने से पहले ललन सिंह ने संजय झा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनसे बात कर लीजिए, यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का है। इतना कहते हुए ललन सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए।

उसके बाद मीडियाकर्मी संजय झा की ओर मुखातिब हो गए। उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी टाल दिया। संजय झा कोई उत्तर दिए बगैर आगे की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह को जेडीयू से छह साल के लिए बाहर करने का कार्यालय आदेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम से जारी किया गया। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पीकर को सौंपा है। यह सवाल राजनैतिक गलियारे में तैर रहा है कि अनंत सिंह पर की जा रही कार्रवाई पर किसने मुहर लगाई। जदयू ने अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी पर भी कड़ी कार्रवाई की है। उनकी जदयू से उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद बीस सूत्री समिति से भी बाहर कर दिया गया है। उनका उपमंत्री का दर्जा भी वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही उनके नाम से आवंटित एक मॉल रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है।

जदयू के बड़े नेता हैं ललन सिंह

ललन सिंह जदयू के बड़े और प्रभावी नेता हैं जो नीतीश कुमार की कोर टीम में शामिल हैं। वे पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जाता है कि अनंत सिंह को ललन सिंह का सपोर्ट मिलता है। विधानसभा चुनाव के समय जब अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल चले गए तो ललन सिंह ने मोकामा की कमान संभाला। पिछले दिनों एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह अपनी पार्टी के नेता नीरज कुमार के खिलाफ उतर गए तो ललन सिंह को ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई। ललन सिंह का बयान आया कि अनंत सिंह अब कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन, अनंत सिंह दो-तीन दिनों के बाद ही पुराने रंग में आ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ललन सिंह को नहीं जानते हैं।

बीपीएससी टीआरई-4 भर्ती : 33,320 शिक्षक पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 3 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

पटना (संवाददाता)। बिहार में सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई-4 को लेकर नई सूचना जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के शिक्षा विभाग के स्कूलों में कुल 33,320 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जानी है। आयोग की ओर से जारी नई जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अब 3 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन और शुल्क भुगतान की तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने और आवेदन शुल्क जमा करने की समयसीमा का उल्लेख किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 33,320 शिक्षक पदों को भरा जाना है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आवेदन की तारीख में बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।

बीपीएससी की नई सूचना के अनुसार, टीआरई-4 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख अब 3 नवंबर 2026 तय की गई है। पहले निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय मिलेगा। हालांकि, इस अतिरिक्त समय का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को नई अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरने चाहिए। फॉर्म में दी गई जानकारी सही हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अपने भरे हुए विवरणों की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए, ताकि किसी तरह की गलती की आशंका कम हो सके।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के साथ ही आयोग ने आवेदन शुल्क जमा करने की समयसीमा भी स्पष्ट कर दी है। बीपीएससी के अनुसार, टीआरई-4 के लिए आवेदन शुल्क 2 नवंबर 2026 तक जमा किया जा सकेगा। यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क भुगतान के लिए अलग-अलग अंतिम तारीखें निर्धारित की गई हैं।

अभ्यर्थियों को इस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि आवेदन भरने के लिए 3 नवंबर तक का समय मिलने का अर्थ यह नहीं है कि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी वही है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से जुड़ी प्रक्रिया 2 नवंबर तक पूरी कर लेनी चाहिए। अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन और भुगतान की औपचारिकताएं पूरी करना अधिक उचित रहेगा।

बिहार विधान परिषद चुनाव

5 शहरों में 8 सीटों की मतगणना, सुबह 8 बजे खुलेगी किस्मत; शाम तक आएंगे नतीजे

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए आठ केंद्रों पर तैयारियां पूरी, स्नातक सीटों पर 14 और शिक्षक सीटों पर सात मेजों पर होगी वोटों की गिनती; दूसरी वरीयता के मतों से तय होगा कई सीटों का परिणाम



पटना (संवाददाता)। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद अब मंगलवार, 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की निगाहें मतगणना केंद्रों पर टिकी हैं। चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों के लिए पांच शहरों में आठ मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होगी। मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम तक चुनाव परिणाम सामने आने की संभावना है।

इन चुनावों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटें शामिल हैं। मतगणना के लिए संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आयोग की ओर से मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मतगणना केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को सभी आठ सीटों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी।

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा और छपरा में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए कुछ शहरों में अलग-अलग केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती संबंधित निर्धारित केंद्रों पर होगी।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती कहां होगी?

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए मतगणना केंद्रों का निर्धारण किया गया है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूर्णिया स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में होगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी कॉलेज के प्रशासनिक भवन में की जाएगी।

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पटना के बांकीपुर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगी। वहीं, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती दरभंगा स्थित खेल भवन सह व्यायामशाला के प्रथम तल पर की जाएगी।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन केंद्रों पर होगी मतगणना

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए भी अलग-अलग मतगणना केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना छपरा स्थित एसवीएन राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी के प्रशासनिक भवन में की जाएगी। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना बांकीपुर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती दरभंगा स्थित खेल भवन सह व्यायामशाला के दूसरे तल पर की जाएगी। इस तरह पांच शहरों में आठ केंद्रों पर मतगणना की व्यवस्था की गई है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के चुनावी भविष्य का फैसला इन्हीं केंद्रों पर मतों की गिनती पूरी होने के बाद होगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, मंगलवार सुबह आठ बजे सभी आठ सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मतगणना पूरी होने के बाद शाम के समय परिणाम सामने आने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक परिणाम घोषित होने में लगने वाला समय मतों की संख्या और मतगणना की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इन चुनावों में मतदान मतपत्रों के माध्यम से हुआ है। इसलिए मतगणना की प्रक्रिया सामान्य चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की गिनती से अलग होगी। इसमें मतदाताओं की ओर से दी गई प्रथम और दूसरी वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। निर्धारित नियमों के अनुसार, विजेता का फैसला करने के लिए मतों का कोटा तय किया जाएगा।

कैसे होगी मतों की गिनती और कैसे तय होगा विजेता?

बिहार विधान परिषद की इन सीटों के चुनाव में मतपत्रों के जरिए मतदान हुआ है। मतगणना के दौरान सबसे पहले कुल वैध मतों की संख्या निर्धारित की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार जीत के लिए आवश्यक मतों का कोटा तय होगा। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में कुल वैध मतों के आधार पर निर्धारित कोटे की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कुल 10 हजार वैध मत पड़े हैं, तो दिए गए विवरण के अनुसार कोटे की गणना 5 हजार मतों के आधार पर की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों को मिले प्रथम वरीयता के मतों की गिनती होगी। यदि किसी प्रत्याशी को निर्धारित कोटे के बराबर या उससे अधिक मत मिल जाते हैं, तो वह जीत की स्थिति में पहुंच सकता है।

यदि प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद कोई प्रत्याशी निर्धारित कोटा हासिल नहीं कर पाता है, तो नियमानुसार सबसे कम मत पाने वाले प्रत्याशी को बाहर करने और उसके मतों को आगे की वरीयता के अनुसार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गणना की जाती है और पात्र प्रत्याशियों के मतों में उन्हें नियमानुसार जोड़ा जाता है।

यह प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है, जब तक किसी प्रत्याशी को निर्धारित नियमों के अनुसार जीत के लिए आवश्यक मत प्राप्त नहीं हो जाते। इसी कारण इन चुनावों में मतगणना की प्रक्रिया में समय लग सकता है और अंतिम परिणाम आने में शाम तक का समय लगने की संभावना जताई गई है।

मतगणना की व्यवस्था के तहत स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती के लिए 14 मेजें लगाई जाएंगी। इन मेजों पर मतपत्रों की गिनती और संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती के लिए सात मेजों की व्यवस्था की गई है।

सभी आठ सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू होगी। इसके लिए मतगणना कर्मियों और प्रेक्षकों की तैनाती की जा चुकी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं।

प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें परिणाम पर

23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद अब सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को मतगणना का इंतजार है। मंगलवार को शुरू होने वाली मतों की गिनती के बाद यह स्पष्ट होगा कि किस निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रत्याशी को बढ़त मिली है और कौन जीत दर्ज करने में सफल रहा है। मतपत्रों के जरिए हुए चुनाव और वरीयता आधारित मतगणना की प्रक्रिया के कारण परिणाम घोषित होने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में सुबह मतगणना शुरू होने के बाद शुरुआती रुझानों और अंतिम परिणामों के बीच अंतर रह सकता है।

आठ सीटों के लिए आज निर्णायक दिन

बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए मंगलवार, 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा और छपरा के आठ केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 14 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सात मेजों पर मतगणना की व्यवस्था की गई है। प्रथम वरीयता के मतों के बाद आवश्यकता पड़ने पर दूसरी वरीयता के मतों की गणना भी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम तक परिणाम आने की संभावना है।

राहुल बने बिहार कांग्रेस के जोनल मीडिया कोर्डिनेटर, नालंदा के प्रभारी भी हैं कुर्मी नेता



पटना (संवाददाता)।

बिहार कांग्रेस ने युवा कुर्मी नेता राहुल कुमार को मीडिया विभाग का जोनल कोर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रहे राहुल कुमार फरवरी में बड़ी संख्या में रालोमो के नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजदूगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कुछ दिन पहले ही राहुल कुमार को नालंदा जिला का प्रभारी बनाया था। नई नियुक्ति के बाद राहुल कुमार को नालंदा के प्रभार के अलावा मीडिया विभाग में जोन की जिम्मेदारी भी दी गई है। राहुल कुमार मगध इलाके के ही शेखपुरा के रहने वाले हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का प्रभारी बनाने में पार्टी ने उनके जातीय बैकग्राउंड पर गौर किया था।

राहुल कुमार राजनीति में सक्रिय होने से पहले लंबे समय तक दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पत्रकारिता का प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। मीडिया विभाग में उनकी तैनाती को राहुल कुमार के अनुभवों का पार्टी हित में इस्तेमाल करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल कुमार के पिता जितेंद्र नाथ शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता रहे, जो वामपंथी दल को छोड़ने के बाद समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) से जुड़े। कुशवाहा ने रालोसपा का जब जदयू में विलय किया, तब वो उनके साथ जेडीयू में गए। जब कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर रालोमो बनाया तो जितेंद्र नात पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, जिस पद पर वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने तक रहे।

शेखपुरा इलाके में पहाड़ बचाने से लेकर पेड़ लगाने तक के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े जितेंद्र नाथ और राहुल कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेखपुरा में पार्टी की ताकत बढ़ी है, जो एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजो सिंह शेखपुरा से ही विधायक बनते रहे और बाद में बेगूसराय लोकसभा से सांसद भी रहे। राजो सिंह के बाद उनके बेटे संजय सिंह और बहू सुनीला देवी भी लगातार 2-2 बार शेखपुरा से विधायक रहे। उनके बाद से यह सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई है। राजो सिंह के परिवार के बाद तीन बार जदयू और एक बार राजद को शेखपुरा में जीत मिली है।

राघोपुर के दो पीपा पुल चालू कराने की मांग, तेजस्वी यादव ने मंत्री को लिखा पत्र

वैशाली (संवाददाता)। राघोपुर और बिदुपुर प्रखंड के लोगों की आवागमन संबंधी समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पथ निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र लिखा है. 26 अक्टूबर 2026 को लिखे गए पत्र में उन्होंने दोनों पीपा पुलों को जल्द चालू कराने और क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानियों से राहत दिलाने की मांग की है.



तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को प्रतिदिन आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. पीपा पुल चालू नहीं होने से लोगों को बाजार आने-जाने, दैनिक कामकाज और आपातकालीन परिस्थितियों में परेशानी होती है. उन्होंने बिदुपुर प्रखंड के जमींदारी घाट-चकोसन पीपा पुल और कच्ची दरगाह घाट से रस्तामपुर घाट के बीच स्थित पीपा पुल का उल्लेख करते हुए इन्हें जल्द चालू कराने की जरूरत बतायी है.

पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बरसात समाप्त होने के बाद सितंबर में ही पीपा पुलों को आवागमन के योग्य बना दिया जाना चाहिए था. लेकिन अक्टूबर का महीना समाप्त होने को है और अब तक पुलों को चालू करने की प्रक्रिया धरातल पर शुरू नहीं हो सकी है. उन्होंने पिछले वर्षों में भी विभागीय सुस्ती के कारण पीपा पुल चालू होने में देरी का मुद्दा उठाया. उनके मुताबिक, इस देरी के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी थी. तेजस्वी यादव ने पत्र में नाव से आवागमन के दौरान डूबने की घटनाओं में लोगों की जान जाने का भी जिक्र किया है. उन्होंने संबंधित मंत्री से नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर दोनों पीपा पुलों पर आवागमन जल्द सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके. राघोपुर और बिदुपुर क्षेत्र के लोगों के लिए पीपा पुल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के कामकाज से भी जुड़ा है.

बिहार में जमीन देने पर मिलेगा चार गुना तक मुआवजा, 10% अतिरिक्त राशि भी देगी सरकार

पटना (संवाददाता)। बिहार सरकार ने रैयती भूमि क्रय नीति-2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सड़क, पुल, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल और दूसरी सरकारी परियोजनाओं के लिए निजी जमीन मालिकों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जाएगी. जमीन के बदले मुआवजे के साथ 10% प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है.

नई नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मालिकों को बाजार मूल्य या सर्किल रेट में से जो अधिक होगा, उसका चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में जमीन के लिए दो गुना तक मुआवजे का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जमीन मालिकों को तय मुआवजे के ऊपर 10% प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. सरकारी इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क भी नहीं लगेगा.

नई नीति में जमीन खरीदने के फैसले के लिए परियोजना की लागत के आधार पर व्यवस्था की गई है. 100 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने का फैसला जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति करेगी. वहीं, 100 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के लिए फैसला प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति लेगी. इस तरह परियोजना की लागत के हिसाब से जमीन खरीदने की मंजूरी देने वाली समिति तय होगी.नीति में जमीन मालिकों की सहमति को अहम रखा गया है. इसके तहत सरकार जमीन का जबरन अधिग्रहण करने के बजाय सीधे खरीद करेगी. जमीन मालिक और सरकार के बीच आपसी सहमति से सौदा होने का प्रावधान है. इस व्यवस्था का मकसद जमीन खरीद के दौरान लंबे कानूनी विवादों से बचना है. सड़क, पुल, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र और अस्पताल जैसी जनहित की परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत जमीन खरीदी जा सकेगी.

बिहार सरकार के पास अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन लेने के तीन विकल्प होंगे. पहला विकल्प रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत आपसी सहमति से जमीन खरीदना है. दूसरा विकल्प जमीन का अधिग्रहण करना है. इस व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जमीन मालिकों को क्रमशः चार गुना और दो गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान है. तीसरा विकल्प लैंड पुलिंग है. इसमें जमीन मालिकों से ली गई जमीन का 55% हिस्सा विकसित करके उन्हें वापस देने की व्यवस्था बताई गई है. इस जमीन पर सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके बाद जमीन की कीमत बढ़ने का लाभ जमीन मालिकों को मिल सकता है.

नई नीति के लागू होने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग पटना और गया में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए किसानों से सीधे बातचीत कर रहा है. किसानों को जमीन देने के तीनों विकल्पों की जानकारी दी जा रही है.

बिहार के पूर्व मंत्री की पत्नी पर जानलेवा हमला, लालू-राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे गजेंद्र प्रसाद सिंह



शिवाजीनगर (संवाददाता)। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी उर्मिला सिन्हा पर बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। समस्तीपुर में उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। बचाव करने में उनकी अंगुली में चाकू लग गया। एक नकाबपोश बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया और शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना स्थल से चप्पल बरामद किया गया है। 2015 में गजेन्द्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे।

घटना शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव में रविवार की देर रात की है। उर्मिला सिन्हा के घर में एक नकाबपोश युवक घुस गया और डराने-धमकाने के बाद चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़िता ने शिवाजीनगर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने, आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उर्मिला सिन्हा से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार की रात करीब 10 बजे टीवी देखने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थीं। इस दौरान कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। लेकिन उन्हें लगा कि पड़ोस में किसी मेहमान के आने के कारण आवाज हो रही है। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। रात करीब दो बजे जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश युवक उनके बिस्तर के पास बैठा हुआ था और उनका मोबाइल उठाने का प्रयास कर रहा था। अचानक कमरे में अजनबी को देखकर वह घबरा गईं। पूछने पर युवक ने उन्हें चाकू दिखाकर चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उन्होंने युवक से पूछा कि वह घर के अंदर क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि उसे सुपारी दी गई है। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले ही युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलने के बाद रोसड़ा एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा दल बल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शिवाजीनगर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल से एक चप्पल भी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद वारिसनगर के पूर्व विधायक अशोक कुमार मुन्ना, पूर्व मंत्री सह उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता और दरभंगा के पूर्व मंत्री ललित यादव ने उनसे संपर्क कर घटना की जानकारी ली।

कौन थे गजेन्द्र प्रसाद सिंह?

गजेन्द्र सिंह समस्तीपुर के रोसड़ा से कई बार विधायक रहे। वे 1986 में पहली बार विधायक चुने गए जब समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने लोकदल के टिकट पर उन्हें उपचुनाव लड़ाया। 1990 में उन्होंने जनता दल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज किया। 1995 में भी वे चुनाव जीत गए। लालू यादव की सरकार में उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं तब भी वे मद्य निषेध विभाग के मंत्री बनाए गए। उन्होंने फरवरी 2005 के आम चुनाव और अक्तूबर 2005 के मध्यावधि चुनाव राजद के टिकट पर रोसड़ा में जीत हासिल किया। 2010 के आम चुनाव में उन्हें जदयू के अशोक कुमार ने हरा दिया। सितम्बर 2015 में 61 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।

विश्वासमत के समय पाला बदलने वाले विधायकों पर कसा तंज, तेजस्वी बोले- सबका हुआ बुरा हाल



पटना (संवाददाता)।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने विश्वास मत के दौरान समर्थन देने वाले विधायकों और नेताओं का जिक्र करते हुए राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा है. उन्होंने आनंद मोहन, प्रह्लाद यादव और अनंत सिंह की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय ही उन्होंने आगाह किया था कि जिन लोगों को समर्थन दिया जा रहा है,वक्त आने पर इसका परिणाम सामने आएगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विश्वास मत पारित होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी, तब उनके तीन विधायकों में नीलम देवी और प्रह्लाद यादव और चेतन आनंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि वे जिस पक्ष को समर्थन दे रहे हैं, समय बताएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है.

तेजस्वी ने मौजूदा राजनीतिक हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि आज आनंद मोहन परेशान हैं, जबकि प्रह्लाद यादव को टिकट तक नहीं मिला. उन्होंने अनंत सिंह की स्थिति का भी जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि उनकी मौजूदा परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए. तेजस्वी यादव के इस बयान को विश्वास मत के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम और नेताओं के मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने अपने पुराने बयान का हवाला देकर यह संदेश देने की कोशिश की कि उस समय दी गई चेतावनी अब सही साबित होती दिख रही है. 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में विश्वासमत के दौरान राजद के तीन विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रह्लाद यादव तीनों ने राजद से अपना समर्थन खीच लिया और विश्वासमत के दौरान जदयू को अपना समर्थन दे दिया. और ये तीनों सता पक्ष के तरफ जाकर बैठ गये और नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई

जब अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से विधायक नीलम सिंह नीतीश कुमार के तरफ जाकर बैठ गयी तो तेजस्वी यादव ने बड़े ही भावुक होकर कहा कि नीलम जी आप एक महिला है, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, बात बने या ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा. साथ में ये भी कहा कोई आए या ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा. इन दिनों ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते दिख रहा है.

अभिजीत दीपके का करियर खत्म, मैं सिर्फ नेहा बोरा की इज्जत करता हूं: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में रहने वाले मार्कंडेय काटजू ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके समेत चार नेताओं के पीस बॉन्ड साइन करने को लेकर उन पर निशाना साधा है और दावा किया है कि इससे उनका करियर खत्म हो गया। काटजू ने आइसा की छात्रनेता नेहा बोरा की पीस बॉन्ड साइन न करने के लिए तारीफ की और कहा है कि वह उनकी इज्जत करते हैं।



मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कॉकरोच जनता पार्टी के चार टॉप लीडर, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे सभी ने पीस बॉन्ड पर साइन किए हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी भी पब्लिक प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, नहीं तो पुलिस कहेगी कि उन्होंने शांति भंग करके अपने बॉन्ड तोड़े हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद लंबे समय के लिए जेल में बंद कर देगी।'' सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने आशंका जताई कि पीस बॉन्ड पर साइन करने की वजह से चारों का पब्लिक करियर अब खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा, ''मेरी राय में पीस बॉन्ड पर साइन करने से इन चार लोगों का पब्लिक करियर खत्म हो गया है, क्योंकि जनता की नजर में उनकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, जो अब उन्हें कायर मानती है जो जेल जाने से डरते हैं। असल में, उन्हें सहयोगी माना जाएगा, क्योंकि उन्हें उन लोगों की तरह माना जाएगा जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने जेल में डाला था, और जिन्हें माफी मांगने पर रिहा कर दिया गया था।'' काटजू ने नेहा बोरा की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''मैं सिर्फ नेहा बोरा की इज्जत करता हूं जिन्होंने पीस बॉन्ड देने से मना कर दिया है।

हाल ही में रिहा हुए रांका और दास

बता दें कि दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया था। दोनों ने हलफनामा दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और जब तक जंतर-मंतर अधिसूचित धरना स्थल नहीं है, तब तक वहां विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। दास और रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया। दोनों ने मुचलके भर दिए, जिसके बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रही सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रितु राज ने सीजेपी नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने स्वागत के लिए इकट्ठा हुए समर्थकों का अभिवादन किया।

दो दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

तबाही मचाने बढ़ा चक्रवात अर्नब का खतरा, आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका; 140 किमी प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान अर्नब में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान आने वाले दिनों में और अधिक शक्तिशाली हो सकता है। 28 अक्टूबर को इसके आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर एहतियाती तैयारियां तेज कर दी गई हैं।



ओडिशा के चार जिलों में भी खतरा

चक्रवात अर्नब का असर ओडिशा में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर के लिए मल्कानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ और गंजाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात अर्नब 28 अक्टूबर को दोपहर तक आंध्र प्रदेश के बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। कुछ समय के लिए हवा की गति बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान की तीव्रता बढ़ने की आशंका को देखते हुए तटीय इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही कृषि और अन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार, 26 अक्टूबर को बताया कि पूर्वी-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा। इसके बाद यह और अधिक तीव्र होकर चक्रवाती तूफान अर्नब में बदल गया। सोमवार सुबह 5:30 बजे तूफान पूर्वी-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था।

उस समय यह श्री विजयपुरम से लगभग 590 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम, ओडिशा के गोपालपुर से 610 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से 650 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व और काकीनाडा से 730 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था। इसके अलावा तूफान मछलीपट्टनम से लगभग 830 किलोमीटर पूर्व और बापटला से 910 किलोमीटर पूर्व में था। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान की दिशा और तीव्रता पर लगातार नजर रखी जा रही है। चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 28 अक्टूबर को एलुरु, एनटीआर, कृष्णा, कोनासीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में अत्यधिक खराब मौसम की आशंका जताई गई है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

29 अक्टूबर के लिए भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पहले से प्रभावित जिलों के अलावा गुंटूर, अल्लुरी सीताराम राजू, अनकापल्ली और विशाखापत्तनम शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। चक्रवात को लेकर राज्य में कृषि विभाग भी तैयारियों में जुटा है। खबरों के मुताबिक, 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कृषि अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चक्रवात और भारी बारिश का दौर गुजरने के बाद खेतों का निरीक्षण किया जाए और फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री केवी सिंह देव ने शनिवार को चक्रवात और भारी बारिश से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को संभावित नुकसान पर नजर रखने और प्रभावित किसानों तक जल्द सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों को नुकसान होने की स्थिति में उसका आकलन कर प्रभावित किसानों को राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। चक्रवात अर्नब की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए अगले दो दिन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तटीय इलाकों में तेज हवाओं, भारी बारिश और संभावित व्यवधानों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमान के आधार पर प्रशासन की तैयारियां और एहतियाती कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं।

27 अक्टूबर को और भी शक्तिशाली हो सकता है चक्रवात

मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवात अर्नब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक ताकतवर हो सकता है। सोमवार की मध्य रात्रि तक इसके भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई गई है। वहीं, 27 अक्टूबर को इसके बहुत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। यदि तूफान की तीव्रता अनुमान के मुताबिक बढ़ती है, तो तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को सतर्क रहने की जरूरत है।

छात्रों के आगे झुका जामिया प्रशासन

20 साल बाद करवाने जा रहा चुनाव; मान लीं 3 मांगें

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 साल के बाद छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्र संघ संविधान की अनुमति के बाद 15 दिनों के भीतर जामिया में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने सोमवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छात्र संघ संविधान की मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे।

बीते कई दिनों से चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह घोषणा की गई है। बीते कई दिनों से छात्र लगातार संघ बहाल करने की मांग कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2006 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र संघ को भंग कर दिया था। छात्र संघ भंग होने के बाद से ही इसकी बहाली को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुका है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा ऐलान करते हुए चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है।

जामिया प्रशासन के इस ऐलान को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को आदेश जारी करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कहा कि छात्र संघ संविधान की मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन के आदेश भी वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा की गई बर्बरता की जांच की जाएगी, जिसके लिए कमेटी गठित की जाएगी।

जामिया प्रशासन ने बताया कि छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, ऐसे में प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान की सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए ऐसे बयानों को भी डिलीट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने बताया कि छात्रों ने प्रदर्शन को खत्म करने की बात भी मान ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इससे पहले, प्रदर्शन स्थल पर बढ़ते तनाव के बीच सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने की घोषणा की थी। प्रशासन ने छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में आने से बचने की सलाह भी दी थी और कहा था कि अगले आदेश तक विश्वविद्यालय के द्वार और पुस्तकालय बंद रहेंगे। प्रशासन ने बताया था कि प्रोफेसरों की सात सदस्यीय समिति ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की थी।

हूतियों ने सऊदी अरब को फिर बनाया निशाना

रियाद एयरपोर्ट और 2 नौसैनिक ठिकानों पर अटैक

यमन (एजेंसी)। सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमलों का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन के हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के तीन महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। इनमें राजधानी रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस और जिजान में स्थित एक नौसैनिक अड्डा शामिल है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक, यमन की सशस्त्र सेनाओं ने तीन अलग-अलग सैन्य अभियानों के तहत दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। उन्होंने दावा किया कि मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाया। हालांकि, इन हमलों में हुए नुकसान और हताहतों को लेकर स्वतंत्र पुष्टि सामने आना बाकी है।



हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि पहले सैन्य अभियान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक, इस हमले में मिसाइलों ने निर्धारित लक्ष्य को भेदा। हूतियों ने अपने दूसरे सैन्य अभियान में दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब के खमीस मुशैत स्थित किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। याह्या सरी के अनुसार, इस अभियान में लड़ाकू विमानों के हैंगर, गोला-बारूद के भंडार, ड्रोन नियंत्रण केंद्र और एयरबेस के अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। हूती प्रवक्ता ने इन हमलों को सटीक बताया । हूतियों के मुताबिक, तीसरा सैन्य अभियान सऊदी अरब के जिजान क्षेत्र में स्थित दक्षिणी नौसैनिक अड्डे के खिलाफ चलाया गया। यह इलाका यमन की सीमा के नजदीक है। याह्या सरी ने दावा किया कि हमले में नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया गया और सऊदी अरब के कई सैनिक तथा अधिकारी मारे गए या घायल हुए।

जेडीयू ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा, 20 सूत्री समिति से हटाया



मोकामा (एजेंसी)। जनता दल (यूनाइटेड) ने अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर एक और बड़ा ऐक्शन लिया है। मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी को अब 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से भी हटा दिया गया है। इससे पहले जदयू ने उन्हें दलविरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। नीलम देवी को 20 सूत्री सदस्य कमेटी से हटाए जाने के बाद उनसे राज्य मंत्री का दर्जा भी छिन गया है।

इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। मोकामा में 'छोटे सरकार' के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह ने 2022 में अपनी पत्नी नीलम देवी को राजनीतिक विरासत सौंपी थी। उस समय यूएपीए के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 2020 में उन्हें और दो साल बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया था। हालांकि, नीलम देवी 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गईं। बताया जाता है कि उन्होंने यह कदम कथित तौर पर अपने पति की सहमति से उठाया था। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुनर्गठित 'राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति' में सदस्य बनाए जाने के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल हुआ था। लेकिन अब यह दर्जा खत्म हो चुका है।

सूत्रों के मुताबिक नीलम देवी के 20 सूत्री समिति से हटने के बाद उनका राज्य मंत्री का दर्जा भी खत्म हो गया है। इस हैसियत से उन्हें मिला पटना का वह सरकारी बंगला भी आगे छिन सकता है, जिसमें अनंत सिंह लंबे समय से रह रहे हैं। बताया जाता है कि यह बंगला नीलम देवी के नाम पर ही आवंटित है। इसी बंगले में अनंत सिंह वो मिठाइयां बनवा रहे हैं जो एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह की जीत के जश्न में बांटने की तैयारी में हैं। अनंत सिंह को बतौर विधायक जो फ्लैट मिला है, उसमें वो नहीं गए हैं। अगर सरकार आगे बंगला खाली करवाती है तो अनंत सिंह को विधायक फ्लैट या निजी आवास में शिफ्ट होना पड़ सकता है।

अनंत सिंह ने जन सुराज प्रत्याशी के लिए किया था प्रचार

अनंत सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए प्रचार शुरू करके जद (यू) के खिलाफ कथित तौर पर बगावत का रुख अपना लिया था। उन्होंने अनुज सिंह का समर्थन और उनके पक्ष में प्रचार करके विधान परिषद चुनाव में जद (यू) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को 'हराने' का संकल्प लिया था। जद (यू) ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी की। जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि पार्टी की पूर्व विधायक नीलम देवी (सिंह की पत्नी) की प्राथमिक सदस्यता भी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 से पहले रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन से मुलाकात की।

भीम ऐप की मीठी दिवाली पहल, हर सातवें लेन-देन से बच्चों की शिक्षा को मिलेगा सहारा

रांची (एजेंसी)। भीम पेमेंट्स ऐप ने मीठी दिवाली 2026 अभियान के तीसरे संस्करण के तहत सामाजिक संस्था गूंज के साथ साझेदारी की है। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में उपयोगकर्ताओं के हर सातवें लेनदेन पर जरूरतमंद बच्चों को स्कूल किट उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। एनपीसीआई भीम की इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बच्चों की शिक्षा से जोड़ना और उन्हें पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करना है। अभियान के जरिए लोगों को रोजमर्रा के भुगतान के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल करने और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एनपीसीआई भीम के कारोबार प्रमुख गौरव कोचर ने कहा कि दिवाली की असली खुशी दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। वहीं, गूंज के संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक अंशु गुप्ता ने इसे तकनीक और सामाजिक भागीदारी का बेहतर उदाहरण बताया। सोचीयर्स के सह-संस्थापक एवं सीईओ मेहुल गुप्ता ने भी त्योहारों की खुशियां साझा करने और डिजिटल लेनदेन के जरिए सामाजिक योगदान देने की पहल की सराहना की।

खाना न बनाने पर पत्नी की हत्या, सबूत मिटाने के लिए घर में ही दफनाया शव

चाईबासा (एजेंसी)। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पत्नी की हत्या करने और उसका शव अपने ही घर के भीतर दफनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना तब सामने आई जब ग्रामीणों ने दंपत्ति की बेटी को उसकी मां गुरुबारी हांसदा के पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सूचना दी। मां के लापता होने की जानकारी मिलने पर बेटी नगिश्री गागराई पंद्राशाली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुंगी गांव स्थित अपने घर पहुंची, लेकिन उसे अपनी मां वहां नहीं मिली। किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उसने अपने पिता राम हांसदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बेटी ने आरोप लगाया कि पिता ने कुल्हाड़ी से मारकर मां की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को घर में दफना दिया।

ओडिशा को इंडिया केम 2026 में 53,893 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि इंडिया केम 2026 में शामिल होने के लिए उनकी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान नौ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और चार निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे राज्य में 53,893.51 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है और 20,210 नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना बनी है। टीम ओडिशा का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री माझी, केमिकल और पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद भुवनेश्वर लौट आए। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार और फिक्की (एफआईसीसीआई) के साथ अगले साल ओडिशा में इस सम्मेलन की मेजबानी करने को लेकर चर्चा की थी, और दोनों ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। इस मौके पर माझी ने यह भी घोषणा की कि अगले साल अक्टूबर में ओडिशा केम 2027 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कारोबारी दिग्गजों के साथ 25 आमने-सामने (वन-टू-वन) बैठकें हुईं। उन्होंने पोस्को इंडिया, जेएसडब्ल्यू और एलएंडटी जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ भी चर्चा की।

इस कार्यक्रम के दौरान हुए प्रमुख समझौतों (एमओयू) में से एक के तहत, ओडिशा सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह समझौता केमिकल और ऊर्जा क्षेत्र में 36,763.51 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए किया गया है।

माझी ने कहा, इन चर्चाओं के जरिए, उनकी जरूरतों को समझने के साथ-साथ उन्हें यह भी पता चला कि ओडिशा में निवेश करने के लिए क्या सुविधाएं और अवसर मौजूद हैं। इससे संभावित निवेशकों के साथ बेहतर समझ बनाने में मदद मिली है। इन कंपनियों की ओडिशा में निवेश करने में गहरी रुचि है।

मुख्यमंत्री ने कंपनियों के साथ इन चर्चाओं को संभव बनाने में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री माझी ने आगे कहा, इस सम्मेलन ने हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धातु-आधारित से बदलकर रसायन-आधारित बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद की है। ओडिशा में धातु, मेटल डाउनस्ट्रीम, रसायन, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक जैसे सभी प्रकार के परस्पर जुड़े उद्योगों की स्थापना करके एक संपूर्ण औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे ओडिशा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में एक मजबूत स्तंभ बन सकेगा।

दिवाली से पहले औंधे मुंह गिरे भाव, सोने में आई गिरावट, चांदी हुई 16 हजार रुपये सस्ती

नई दिल्ली (एजेंसी)। फेस्टिव सीजन में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिवाली और धनतेरस से पहले दोनों कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार से लेकर वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तक सोने और चांदी की कीमतें नीचे आ गई हैं। बीते सप्ताह के चार कारोबारी दिनों में ही चांदी 16,000 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई, जबकि सोने के भाव में भी हजारों रुपये की गिरावट आई है। चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 2.24 लाख रुपये नीचे आ चुकी है।

दिवाली और धनतेरस से पहले चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार का रुख बदल दिया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, 16 अक्टूबर को चांदी का भाव 2,10,918 रुपये प्रति किलोग्राम था। कारोबार बंद होने तक यह गिरकर 1,94,415 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। इस तरह महज चार कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत 16,503 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गई। इसके साथ ही घरेलू बाजार में चांदी का भाव 2 लाख रुपये के स्तर से नीचे पहुंच गया। वायदा बाजार में भी चांदी की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिली है। MCX पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव 16 अक्टूबर को 2,11,187 रुपये प्रति किलोग्राम था। यह घटकर 1,96,100 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इस हिसाब से वायदा बाजार में चार कारोबारी दिनों के दौरान चांदी 15,087 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। चांदी की कीमत में आई गिरावट का अंदाजा इसके रिकॉर्ड स्तर से लगाया जा सकता है। इस साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का लाइफटाइम हाई छुआ था।

भारत-ईयू एफटीए समझौता व्यापार और निवेश के नए रास्ते बनाने में मदद करेगा, बर्लिन में बोले पीयूष गोयल

बर्लिन (एजेंसी)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया है। यह समझौता इस साल के अंत तक होने वाला है, जो बाजार पहुंच बढ़ाने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और व्यापार तथा निवेश के नए रास्ते बनाने में मदद करेगा।



पीयूष गोयल ने बर्लिन में साथ आए भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत को सार्थक चर्चा बताया। उन्होंने भारत-जर्मनी साझेदारी की बढ़ती गति और भारतीय उद्योग के लिए इसमें मौजूद अवसरों का जश्न मनाया। उन्होंने कारोबारियों, खासकर एमएसएमई से, इस अवसर का लाभ उठाने और जर्मन समकक्षों के साथ स्थायी साझेदारी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने टेक्सटाइल से लेकर फार्मा, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और नई तकनीकों तक के क्षेत्रों का जिक्र किया। पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, प्रतिनिधिमंडल से गुणवत्ता, अनुपालन और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया, ताकि एक ऐसे देश के रूप में भारत की साख मजबूत हो जो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है और एक ऐसा साझेदार है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बर्लिन में प्रमुख जर्मन शोध संगठनों के प्रमुखों के साथ एक गोलमेज बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने बताया, रिसर्च, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत-जर्मनी सहयोग बढ़ाने पर विचार साझा किए। चर्चा में एडवांस्ड मटेरियल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर भी फोकस रहा, साथ ही हमारे रिसर्च संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई।

नई और उभरती औद्योगिक तकनीकों पर काम कर रहे चुनिंदा फ्राउनहोफर संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जर्मन सटीक तकनीक और भारत की कुशल प्रतिभा एक साथ आकर किफायती लागत पर नवाचार को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कौशल विकास के लिए भारत के समर्पित प्रयासों के साथ, शोधकर्ताओं, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी साझेदारी को गहरा करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-ईयू एफटीए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, आईटी और टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी-आधारित सेवाओं में हमारी पूरक ताकतों को जोड़ने के लिए अपार अवसर खोलता है, ताकि हमारे लोगों के लिए अधिक समृद्धि लाई जा सके।

वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते बाजार पर दबाव, हफ्ते भर में सेंसेक्स और निफ्टी में आई 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट

मुंबई (एजेंसी)। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहा। अवकाश के कारण छोटा रहा कारोबारी सप्ताह भी निवेशकों के लिए राहत नहीं ला सका और प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों में लगातार चौथे सत्र गिरावट दर्ज की गई। वहीं पूरे सप्ताह में निफ्टी 50 में लगभग 2.4 प्रतिशत और सेंसेक्स में करीब 2.2 प्रतिशत की गिरावट रही।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 125.56 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 73,123.83 पर और निफ्टी 87.65 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,600.00 पर पहुंच गया।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतें घरेलू बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी हैं। इसी वजह से निवेशकों ने जोखिम वाले निवेशों में अपनी हिस्सेदारी कम की, जिसका असर सिर्फ लार्जकैप शेयरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में और अधिक तेज गिरावट देखने को मिली।

निफ्टी 50 लगातार चार कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद दबाव में बना हुआ है। हालिया बिकवाली ने बाजार की अल्पकालिक तकनीकी संरचना को कमजोर किया है और सूचकांक अपनी पिछली रिकवरी को बरकरार रखने में संघर्ष कर रहा है।

विश्लेषकों के मुताबिक, निफ्टी के लिए 22,800 का स्तर तत्काल प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) के रूप में देखा जा रहा है, जबकि इसके ऊपर 23,000 का स्तर महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं, दूसरी ओर सेंसेक्स के लिए 72,600 से 72,500 का दायरा निकटतम समर्थन (सपोर्ट) क्षेत्र माना जा रहा है। व्यापक बाजार में गिरावट का असर अधिक दिखाई दिया। ऊंचे वैल्यूएशन और लीवरेज्ड पोजिशन में कमी के कारण मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेज करेक्शन आया, जबकि लार्जकैप शेयर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहे।

सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ही ऐसा रहा जिसने अपेक्षाकृत मजबूती दिखाई। सप्ताह की शुरुआत में बिकवाली के दबाव में रहने के बावजूद बेहतर तिमाही नतीजों और निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण आईटी शेयरों ने सप्ताह लगभग स्थिर स्तर पर समाप्त किया।

इसके विपरीत, ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली हुई, क्योंकि बढ़ती लागत और मार्जिन पर पड़ने वाले



दबाव को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। वैश्विक कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड 3.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 116.72 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो 29 अप्रैल के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 3.8 प्रतिशत बढ़कर 103.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। पूरे सप्ताह के दौरान ब्रेंट क्रूड में 6.2 प्रतिशत और डब्ल्यूटीआई में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे परिवहन और ऊर्जा लागत बढ़ेगी, उपभोक्ता मांग पर असर पड़ेगा और तेल पर निर्भर उद्योगों के मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव आएगा। यही कारण है कि आने वाले हफ्तों में भी निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा कच्चे तेल की चाल और उससे जुड़े वैश्विक घटनाक्रमों पर बनी रहेगी।

सेमीकंडक्टर के लिए 5,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले; 10,000 नौकरियां मिलने की संभावना : सीएम मोहन यादव

इंदौर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश को लगभग 5,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों से 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना है। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

ये प्रस्ताव इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट 2026 में निवेशकों के साथ हुई बैठकों से सामने आए। इस समिट में सरकार ने चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर निर्माण, एडवांस्ड पैकेजिंग और अन्य हाई-टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की अपनी योजनाओं को पेश किया।

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय समिट को संबोधित करते हुए, यादव ने कहा कि कोविड महामारी ने सेमीकंडक्टर के रणनीतिक महत्व और इस क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी ने यह दिखा दिया कि अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इस समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्वीडन के प्रतिनिधियों सहित 1,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने निवेश, प्रौद्योगिकी विकास और कौशल निर्माण पर चर्चा की। यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए 25 से अधिक नीतियां पेश की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य पहलों के माध्यम से लगभग 34 लाख



करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव अब कार्यान्वयन के चरण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 5,000 मेगावाट से बढ़कर 32,000 मेगावाट हो गई है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें तेजी से मंजूरी, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। यादव ने कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, एक बार जब कोई मध्य प्रदेश आता है, तो वह हमेशा के लिए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता है।

सरकार ने एक सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो चिप डिजाइन, वीएलएसआई (वीएलएसआई), अनुसंधान, प्रोटोटाइपिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगा। इसके अलावा, फोटोनिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भी एक अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई। साथ ही, पांच कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) दिए गए। इन परियोजनाओं में 9,625 करोड़ रुपए का निवेश और 4,450 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें ग्वालियर में 50 मेगावाट का हाइपरस्केल डेटा सेंटर, भोपाल में लिथियम-सेल निर्माण इकाई, और इंदौर व भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, सात कंपनियों को इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में ऑफिस स्पेस की पेशकश की गई। इन सुविधाओं से 1,280 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने कौशल विकास, निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग सहयोग में मदद के लिए पांच संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, सेमी इंडिया और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, और मोहाली शामिल हैं।

नीतिश रेड्डी ने बताया ऑलराउंडर के तौर पर वर्कलोड संभालना क्यों है बड़ी चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी चोट मुक्त रहकर खेलना चाहते हैं तथा बल्ले और गेंद दोनों से जिम्मेदारी निभाने के कारण बढ़ने वाले कार्यभार को संभालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेड्डी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 13 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए, एक विकेट लिया और तिलक वर्मा के साथ सातवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। इससे भारत ने रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की।



इस ऑलराउंडर ने स्वीकार किया कि अपने कार्यभार को नियंत्रित करना एक सतत प्रक्रिया है, इसकी चुनौतियां केवल मैच के दिनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अभ्यास सत्रों में भी उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रेड्डी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जैसे-जैसे मैं इस बात को समझ रहा हूं, आप लोगों को भी समझना होगा कि मैं एक ऑलराउंडर हूं। मुझे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करनी होती हैं।

अभ्यास के दौरान भी मुझे अपने कार्यभार का ध्यान रखना पड़ता है। मैदान के अंदर और बाहर मुझे काफी मेहनत करनी होती है।'' रेड्डी का मानना है कि लगातार खेलते रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, ''मैं इसी पर काम कर रहा हूं और कोई भी खिलाड़ी चोटिल नहीं होना चाहता। मैं खुश हूं कि भारतीय टीम के लिए खेल रहा हूं। यह हर दिन की प्रक्रिया है।'' उन्होंने कहा, ''अगर अगले दिन भी मैं मैदान पर उतरकर अपनी टीम के लिए खेल पाता हूं, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा संकेत होगा, चाहे मैं कहीं भी खेलूं। मुझे उम्मीद है कि मैं चोटिल नहीं होऊंगा, लेकिन अभी मैं इस प्रक्रिया से गुजर रहा हूं।'' रेड्डी ने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर द्वारा खिलाड़ियों में जगाया गया भरोसा उन्हें लक्ष्य का पीछा करते समय दबाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में मदद करता है।

उन्होंने कहा, ''वास्तव में कोई खास संदेश नहीं था, लेकिन गौतम सर हमें लगातार कहते रहे कि हम किसी भी स्थिति में हों, हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना है। हमने वही किया और नतीजा सबके सामने है।''

वाणी कपूर तीसरे दौर के बाद एक शॉट आगे

10 साल बाद घरेलू खिताब जीतने की उम्मीद

गुरुग्राम (एजेंसी)। गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में चल रहे हीरो वुमैन इंडियन ओपन के तीसरे दौर में भारतीय गोल्फर वाणी कपूर ने तीन अंडर 69 का कार्ड खेला। वह कुल पांच अंडर 211 के स्कोर के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। अदिति अशोक द्वारा 2016 में जीती गई ट्रॉफी के बाद भारत के पास यह खिताब दोबारा हासिल करने का मौका है। भारतीय गोल्फर वाणी कपूर ने हीरो वुमैन इंडियन ओपन के तीसरे दौर के बाद एक शॉट की बढ़त हासिल कर 10 साल बाद घरेलू चैंपियन बनने की उम्मीदें मजबूत कर दी हैं। पांच लाख डॉलर की इनामी राशि वाले लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) टूर्नामेंट के तीसरे दौर में 32 वर्षीय वाणी ने तीन अंडर 69 का कार्ड खेला। उनका कुल स्कोर पांच अंडर 211 है।

वह गत चैंपियन सिंगापुर की शैनन टैन और थाईलैंड की तीन बार की विजेता पोर्नानॉन्ग फाटलम से एक शॉट आगे हैं। टैन ने तीसरे दौर में 67 जबकि फाटलम ने 69 का कार्ड खेला। भारत की अदिति अशोक ने 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। उसके बाद से कोई भारतीय गोल्फर घरेलू धरती पर यह खिताब नहीं जीत सकी है। डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में वाणी के पास अब इस लंबे इंतजार को खत्म करने का सुनहरा अवसर है। तीसरे दौर में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा रहा। बीमारी और थकान से जूझ रहीं एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता प्रणवी उर्स को तीसरे दौर में थोड़ा नुकसान हुआ। वह तीसरे दौर से पहले संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थीं, लेकिन 73 का कार्ड खेलने के बाद संयुक्त चौथे स्थान पर खिसक गईं। प्रणवी का कुल स्कोर तीन अंडर 213 है।

शाहीन अफरीदी ने रचा इतिहास, 80वें वनडे में हासिल की बड़ी उपलब्धि

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए और इस मुकाम तक सबसे कम मैचों में पहुंचने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बन गए। शाहीन ने वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई।

शाहीन अफरीदी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपने करियर के 80वें वनडे में 150 विकेट पूरे किए। इससे पहले वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने 91-91 मैचों में यह आंकड़ा छुआ था। इस तरह शाहीन पाकिस्तान के सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। मैच से पहले शाहीन को 150 विकेट पूरे करने के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी। उन्होंने इंग्लैंड की पारी के पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन को आउट कर यह मुकाम हासिल कर लिया। बैंटन अच्छी फॉर्म में थे और अपनी पिछली चार पारियों में लगातार चार अर्धशतक से अधिक के स्कोर बना चुके थे। शाहीन की फुल लेंथ गेंद पर बैंटन ने कवर की दिशा में शॉट खेला, जहां अराफात ने आसान कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही शाहीन ने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भी पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को एक और सफलता दिलाई। पाकिस्तान के गेंदबाजों में सबसे कम मैचों में 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड अब भी ऑफ स्पिनर सैकलैन मुश्ताक के नाम है।

कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता खिताब, फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी को रौंदा

नानचांग (एजेंसी)। कैटरीना सिनियाकोवा ने फाइनल में शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और एश्लिन क्रूगर को वापसी का मौका नहीं दिया। उन्होंने महज 64 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। सिनियाकोवा ने पूरे मैच में क्रूगर की सर्विस छह बार तोड़ी और दोनों सेट में अपना दबदबा बनाए रखा।

30 वर्षीय सिनियाकोवा के लिए यह जीत खास रही, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार 2023 में चीन के नानचांग में जियांग्शी ओपन का सिंगल्स खिताब जीता था। जापान ओपन की ट्रॉफी उनके करियर का छठा सिंगल्स खिताब है। उन्होंने पहली बार 2017 में चीन के शेनझेन में एकल खिताब जीतकर अपने करियर की शुरुआत की थी।

सिनियाकोवा को टेनिस में खास तौर पर डबल्स की बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। उनके नाम करियर में 39 डबल्स खिताब हैं। पिछले महीने उन्होंने टेलर टाउनसेंड के साथ यूएस ओपन महिला डबल्स का खिताब भी जीता था। जापान ओपन में मिली जीत ने उनके सिंगल्स करियर को भी नई मजबूती दी है।



संपादकीय

नैरेटिव कंट्रोल की चिंता

हाल में संकेत मिले कि सत्ता पक्ष का नैरेटिव कंट्रोल टूट रहा है। उस नियंत्रण को वापस पाने के हालिया प्रयास कारगर नहीं हुए। तो अब संभवत: सरकार की शक्ति के इस्तेमाल की रणनीति बनी है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीते आठ अक्टूबर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी भेजी। इसमें कहा गया था कि वे दिल्ली में चल रहे राजनीतिक आंदोलनों के सिलसिले में भ्रामक, पुरानी या संदर्भ से अलग सामग्रियों पर कड़ी निगरानी रखें। उसके बाद दस अक्टूबर को मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा को अलग निर्देश भेजा। उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम (एल्गोरिदम) पर सवाल उठाया गया। कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को आगाह किया गया है कि उन पर एकतरफा नैरेटिव जा रहा है, जिसे उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए, जिससे यूजर्स को किसी भी मुद्दे पर एकतरफा जानकारी या सीमित नैरेटिव ना मिले। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को प्रसारण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा कि बहस के लिए गेस्ट के चयन में सावधानी बरती जाए और जरूरत पड़ने पर चैनलों को टिप्पणियां म्यूट करने, चेतावनी दिखाने, डिस्क्लेमर लगाने या प्रसारण रोकने जैसे कदम उठाने चाहिए। सरकार ने आगाह किया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम-1995 और उससे जुड़े प्रोग्राम कोड के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है। संदर्भ सामान्य हो, तो इन परामर्श-पत्रों को सरकार के सामान्य कर्तव्य निर्वहन के रूप में समझा जाता। लेकिन फिलहाल जो पहल हुई है, उसे मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आम समझ बनी है कि कॉकरोच आंदोलन के उदय ने देश में राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है।

अपेक्षाकृत संपन्न घरों से आए नौजवानों ने ऐसी तीखी और अ-शालीन शब्दावली को आम बना दिया, जिससे माहौल बदला और सत्ता पक्ष एवं उसके नेताओं के लिए तब तक अनकही बातें खुल कर कही जाने लगीं। इससे संकेत मिला कि सत्ता पक्ष का नैरेटिव कंट्रोल टूटने लगा है, जो उसकी राजनीतिक शक्ति का प्रमुख आधार रहा है। उस नियंत्रण को वापस लाने के प्रयास पहले हुए, लेकिन वे कारगर नहीं हुए।

ट्रम्प ने मस्क-सीआईए को ही कर दिया एक्सपोज?

इस वक्त अमेरिका के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। दोनों एक ही देश के हैं। दोनों मतलब एलन मस्क ट्रंप की पार्टी का समर्थन करते हैं और ट्रंप के समर्थक भी हैं एलन मस्क। 2024 के चुनाव में भी अच्छी खासी फंडिंग की थी और इस वाले चुनाव में भी हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग की है और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है यूक्रेन। अमेरिका के भीतर महंगाई बढ़ रही है क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। बाब अल मंदेब बंद है। जिसकी वजह से रूस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और वहां से तेल मंगाना पड़ा। अब रूस की रिफाइनरीज के ऊपर यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन हमले कर रहा है। जिन ड्रोन से उन ड्रोन पर स्टार्लिंग की डिवाइस लगी हुई है। उस डिवाइस की मदद से ही यूक्रेन के ड्रोन रशिया को छेद पा रहे हैं। उसकी रिफाइनरी पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसे में आपने पिछले दिनों खबर सुनी कि किस तरीके से स्टार लिंक ने यूक्रेन की स्पीड कम कर दी। आप जो समझते हैं ना डाउनलोडिंग करने की स्पीड इंटरनेट की या फिर कुछ सर्च करने की स्पीड सिर्फ वही स्पीड इंटरनेट की नहीं होती है। हथियारों की एक अलग तरीके की स्पीड होती है। 100 किमी प्रति घंटा 150 किमी प्रति घंटा 200 किमी प्रति घंटा तक की स्पीड होती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा दिक्कत सामने वाले देश को उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में आएंगी। यहां स्टार्लिंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 कि.मी. प्रति घंटा के आसपास थी। तो रशिया के इंटरसेप्टर उन्हें पकड़ नहीं पाते थे और ये ड्रोंस जाकर रिफाइनरीज को हिट कर रहे थे। ट्रंप को रूस के साथडील करनी थी। ऐसे में अब उन्होंने आदेश दिया या नहीं दिया। ऐसे में अचानक से यूक्रेन की स्पीड इंटरनेट वाली कम हो गई। आरोप लगा कि मस्क ने यूक्रेन के मिलिट्री स्टार्लिंग की स्पीड को 100 मील प्रति घंटा पर कैप कर दिया। मतलब 100 मील प्रति घंटा का मान लीजिए कि 160 किमी प्रति घंटे के हिसाब से कैप कर दिया। कैप करने का मतलब है अगर वो ड्रोन 160 कि.मी. प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर जाएगा तो वो उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। उसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। जाएगा। अब जब इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि कहां हिट करना है, कहां हिट नहीं करना है। और जो उसे ऑपरेट कर रहे हैं लोग उनके पास तक वीडियो जब नहीं पहुंचेगा तब



वो लोग भी एक तरीके से अंधे हो जाएंगे। तो ये पूरा गेम किया गया। इससे यूक्रेन के हमलावर ड्रोन रूस के सामने फेल होने लगे और अब वॉल स्ट्रीट जनरल की ब्रेकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो।

ट्रंप का कहना है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एलन मस्क का कहना है कि मेरा भी उसमें कोई रोल नहीं है। रोल सामने आया सीआईए का। स्टार लिंक से डायरेक्ट इंटरनेट नहीं लेता है यूक्रेन। ये लेता है स्टार शील्ड से। स्टार शील्ड के ऊपर मतलब कौन नजर रखता है या फिर किसके हाथ में स्टार शील्ड है। स्टार शील्ड हाथ में है सीआईए के। अब पूरा गेम आपको समझ आया आ गया होगा कि किस तरीके से सिर्फ एक खबर बाहर आने से कि ट्रंप ने खुद मस्क को फोन करके कहा कि यह पाबंदी हटा लो। यहां सीआईए का भी जो पर्दाफाश हो गया और एलन मस्क भी एक्सपोज हो गए। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक यह फोन बुधवार को किया गया। ट्रंप ने मस्क से कहा कि वो इस स्पीड लिमिट से नाराज हैं। यह लिमिट 14 अक्टूबर को स्पेस एक्स ने लगाई थी। यूक्रेन को शक है कि ट्रंप ने रूस की तरफ झुकाव का हिस्सा था। क्योंकि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने मॉस्को से तेल खरीदने और जेलस्की को हटाने की बात कही थी। कारनेगी एंडोमेंट के एक्सपर्ट माइकल कॉफमैन का कहना है कि अगर यह थ्रटल नहीं हटा तो रूस का फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ना फिर तेज हो जाएगा। मतलब यूक्रेन की जंग का रिमोट कंट्रोल आज भी एक प्राइवेट कंपनी और दो लोगों के फोन कॉल पर टिका हुआ है। ट्रंप अब कतई नहीं चाहते कि जेलस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे और वो उन्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

दो हफ्ते पहले तक राहुल गांधी देश में चुनाव चोरी, वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इन सब की मांग कर रहे थे। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप बीजेपी और सरकार पर वह लगा रहे थे। पूरा विपक्ष एक साथ आ गया था। सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा रहा था।

दिल्ली में आकाशवाणी से लेकर राजघाट तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर जंतरमंतर तक जमकर प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर सरकार और पूरे संवैधानिक सिस्टम पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना हर विपक्षी का अधिकार है। सरकार ट्रैक पर रहे यह याद दिलाना विपक्ष का काम है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से डिसक्रेडिट कर देना कहां तक जायज है? राहुल गांधी ने देश में बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया था। सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। बीजेपी, सरकार और बाकी तमाम को आकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ रहा था हर चीज पर। लेकिन जैसे ही इस पूरे सियासी गेम में पीएम मोदी की एंट्री हुई पूरा समीकरण 360 डिग्री चेंज हो गया। पूरा सिस्टम ऐसे पलटा कि अब बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। यह सब बदला है। 18 अक्टूबर को राहुल गांधी के वियतनाम जाने की खबर सामने आने के बाद। राहुल गांधी जैसे ही विदेश पहुंचे, बीजेपी को उनकी विदेश यात्रा और विदेशों में मुलाकातों पर सवालों की झड़ी लगाने का मौका मिल गया। 2020 हो, 22 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, हर बार एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी लेकर आते हैं। भारत यात्रा पर निकलते हैं। छात्रों की गूंज करते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पीएम मोदी के घर के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चीज मोमेंटम पकड़ती है, वो चले जाते हैं। जनता को जुटाते हैं और फिर वर्क फ्रॉम विदेश पर निकल जाते हैं। अगर वोट चोरी गंभीर मुद्दा है तो राहुल गांधी खुद कितने गंभीर हैं? क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की कोई जगह है?

अधिकार देने से पहले सुरक्षा की सोचिए

सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी, मीडिया रिपोर्टों में बताई गई इस टिप्पणी पर कि बच्चों पर इंटरनेट का पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है, गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है। क्या अधिकार की चर्चा करते समय हम उस बच्चे की वास्तविक सुरक्षा को पीछे छोड़ दें, जो स्क्रीन के दूसरी ओर बैठा है? साइबर कानून और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कानून में तीन दशक के काम के अनुभव से मेरा मत स्पष्ट हुआ है। इंटरनेट बच्चों के लिए अवसर भी है और जोखिम भी, पर आज जोखिम इतना बड़ा और तेज है कि कानून को अधिक सतर्क और निर्णायक होना पड़ेगा।

सबसे पहले हम बच्चों के सामने उपस्थित खतरे की बात करें। इसमें पहला खतरा वाहियात सामग्री का है। हिंसा, अश्लीलता और नफरत फैलाने वाली सामग्रियों एक क्लिक की दूरी पर होती हैं। बच्चा उसे खोजता नहीं, कई बार एल्गोरिदम स्वयं उसके सामने ऐसी सामग्री को परोस देता है। दूसरा खतरा ऑनलाइन ग्रूमिंग और यौन शोषण का है। इसमें कोई अपराधी इंटरनेट के माध्यम से किसी बच्चे से दोस्ती करता है, उसका भावनात्मक भरोसा जीतता है और फिर उसका यौन शोषण, ब्लैकमेल या वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए उसके मानस पर नियंत्रण कर लेता है। इसका पता माता-पिता को बिल्कुल नहीं चलता है। तीसरा खतरा साइबर बुलिंग का है। इसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी बच्चे को बार-बार जान-बूझकर परेशान करना, डराना, अपमानित करना या नुकसान पहुंचाना शामिल है। स्कूल की धमकी बच्चे के बिस्तर तक पहुंच जाती है। उसका दुष्प्रभाव बच्चे के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है।

चौथा खतरा लत का है। अनंत स्क्रॉल, ऑटोप्ले और नोटिफिकेशन जैसी डिजाइन तकनीकें जान-बूझकर ध्यान को बांधने के लिए बनाई जाती हैं। वयस्क भी इनसे जूझते हैं, तो विकसित हो रहे बच्चे के मस्तिष्क से बराबरी की अपेक्षा कैसे की जाए? पांचवां खतरा डीपफेक और एआई जनित सामग्री का है। बच्चों की तस्वीरों से बनाई गई छेड़छाड़ वाली सामग्री, एआई चैटबॉट के साथ भावनात्मक निर्भरता और भ्रामक सूचनाएं नए जोखिम हैं, जिनके लिए हमारे कानून अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। छठा खतरा डाटा के शोषण का है। बच्चों की पसंद, लोकेशन और व्यवहार का डाटा इकट्ठा कर उनका विज्ञापन और प्रोफाइलिंग की जाती है। इसमें साइबर ठगी और ऑनलाइन गेमिंग के जरिये होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी भी शामिल है।

हमें समझना चाहिए कि शिक्षा और सूचना जरूरी है, लेकिन अधिकार कभी निरपेक्ष नहीं होते। अपराधी संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों के नाम पर अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में हर अधिकार के साथ युक्तियुक्त प्रतिबंध की अवधारणा जुड़ी है। बच्चों को वयस्कों की तरह मताधिकार, अनुबंध या शराब खरीदने की छूट नहीं है, क्योंकि राज्य का दायित्व है कि वह उन्हें ऐसे निर्णयों से बचाए, जिनके परिणाम समझने की परिपक्वता उनमें अभी विकसित नहीं हुई है। यही तर्क ऑनलाइन दुनिया पर भी लागू होना चाहिए। बच्चे का जीवन और गरिमा का अधिकार, हर सुविधा तक असीमित पहुंच के अधिकार से ऊपर है। यही कारण है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश बच्चों को सोशल मीडिया पर आने से रोक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया खाता रखने के खिलाफ कानून बनाया। इसका मूल संदेश है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी बच्चों और माता-पिता पर नहीं, प्लेटफॉर्म पर डाली जाए। अन्य कई देशों में भी इसी तरह के कानून बन रहे हैं। इन कदमों के पीछे एक साझा समझ है। स्वैच्छिक नियम और कंपनियों के आश्वासन अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। जब तक कानूनी बाध्यता नहीं होती, सुरक्षा व्यावसायिक हितों के बाद आती है। आयु-सीमा बच्चे को सजा नहीं देती, वह प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाती है। भारत का 'डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम-2023' बच्चों द्वारा डाटा उपयोग के लिए सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति का प्रावधान करता है और बच्चों की ट्रैकिंग तथा उनको लक्ष्य कर बनाए विज्ञापन पर रोक लगाता है, पर इसके क्रियान्वयन की चुनौतियां बड़ी हैं। सत्यापन की व्यावहारिक विधि क्या होगी और निजता की रक्षा करते हुए आयु की पुष्टि कैसे होगी, ये प्रश्न अभी हैं। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ अग्रिम उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले, हर आयु वर्ग के लिए अलग-अलग नियम हों। दूसरा, बच्चों के लिए डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित सेटिंग अनिवार्य हों और उल्लंघन पर सार्थक दंड लगे। तीसरा, गोपनीयता का सम्मान करते हुए आयु के सत्यापन की तकनीक विकसित की जानी चाहिए, जो बच्चे की पहचान उजागर किए बिना केवल आयु की पुष्टि करे। चौथा, मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक डिजाइन पर रोक लगे। बच्चों के लिए अनंत स्क्रॉल, ऑटोप्ले प्रतिबंधित हों। पांचवां, एआई के लिए विशेष नियम बनें। छठा, स्कूलों के पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन व्यवहार की शिक्षा शामिल हो और माता-पिता को भी प्रशिक्षित किया जाए। सातवां, बच्चों के विरुद्ध ऑनलाइन अपराध पर सामग्री हटाने की समयबद्ध प्रक्रिया और पीड़ित के लिए सहायता तंत्र हो और आठवां, अंतरराष्ट्रीय सहयोग किया जाए।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे डिजिटल दुनिया से कटें या जुड़ें। प्रश्न यह है कि वे किस उम्र में, किन शर्तों पर और किसकी जवाबदेही के साथ जुड़ें। जब तक तकनीकी कंपनियां बच्चों के लिए सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी नहीं निभातीं, तब तक आयु-आधारित प्रतिबंध एक आवश्यक सुरक्षा कवच है। बच्चों का हित सर्वोपरि है और कानून को इस सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए।

पद्मासन का एडवांस रूप है बद्ध पद्मासन, पाचन से लेकर रीढ़ तक के लिए है रामबाण

योग में ऐसे कई आसन हैं, जो शरीर के साथ-साथ मन को भी स्वस्थ रखते हैं, उन्हीं में से एक है बद्ध पद्मासन। यह आसन पद्मासन का एक एडवांस रूप है, जिसको नियमित रूप से करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और कंधे, पीठ और जोड़ों को मजबूती मिलती है। बद्ध पद्मासन को पद्मासन का एक उन्नत रूप माना जाता है। इसमें पैरों को कमल की तरह मोड़कर हाथों से पीठ के पीछे बांधा जाता है। बद्ध का अर्थ बंधा हुआ और पद्म का अर्थ कमल का फूल होता है। यह आसन शरीर की स्थिरता, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में कारगर होता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह आसन न केवल शारीरिक दृढ़ता बल्कि गहरी मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके नियमित अभ्यास से पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रीढ़ की हड्डी में खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है।

वहीं, आयुष विशेषज्ञों के अनुसार, लेटकर किए जाने पर पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जो पाचन को सुधारता है और कब्ज, अपच, गैस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। बद्ध पद्मासन का अभ्यास सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और ऊर्जा के स्तर पर भी गहरा असर डालता है।

योग शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर में नाड़ियों के जरिए प्राण ऊर्जा प्रवाह करती है। बद्ध पद्मासन में जब पैर आपस में लॉक होते हैं और हाथ पीछे बंधते हैं, तो शरीर में एक ऊर्जा सर्किट बन जाता है। इससे ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि शरीर के अंदर ही घूमकर सभी चक्रों को सक्रिय करती है। यह मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है और यह आसन ध्यान के लिए आदर्श स्थिति बन जाता है।

इस आसन को करने के लिए शरीर में अत्यधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे करने से पहले पद्मासन में महारत हासिल करना आवश्यक है।

मां बनने के बाद प्रेग्नेंसी के दिनों को लेकर करिश्मा तन्ना ने की खुलकर बात



हाल ही में मां बनीं अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने प्रसव के बाद अपने शरीर को लेकर होने वाली परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कभी-कभी उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी से पहले वाली बॉडी की याद आती है और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में आए बदलावों के साथ तालमेल बैठाना उन्हें मुश्किल लगता है। इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने अपने पेट के ढीलेपन, त्वचा के ढीले होने और शरीर के आकार में आए बदलावों के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उनके बच्चे के जन्म को अभी सिर्फ ढाई महीने ही हुए हैं। उन्होंने जिम की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें उनके शरीर में आए बदलावों की झलक देखने को मिली। करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, कभी-कभी, मुझे अपनी प्रेग्नेंसी से पहले वाली बॉडी बहुत याद आती है। जब मैं आईने में देखती हूं, तो मुझे अपना पेट ढीला लगता है, त्वचा ढीली दिखती है और मेरा शरीर पहले के मुकाबले बड़ा हो गया है। शॉपिंग करना बहुत थकाऊ लगता है और कभी-कभी तो मेरा तैयार होने का भी मन नहीं करता।

अभिनेत्री ने कहा, फिर मुझे खुद को प्यार से याद दिलाना पड़ता है। मेरे अंदर एक नन्हा इंसान पल रहा था। मेरे शरीर ने उसकी जिंदगी के लिए जगह बनाई। अभी तो बस ढाई महीने ही हुए हैं, मैं इतनी जल्दी खुद से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रही हूं? मैं अपने शरीर के लिए आभारी भी हो सकती हूं और साथ ही इसमें आए बदलावों को मुश्किल भी मान सकती हूं। मैं मां बनने के अनुभव से प्यार भी कर सकती हूं और साथ ही खुद को महसूस करने की कमी भी महसूस कर सकती हूं।

करिश्मा ने कहा कि माएं भी उसी कोमलता की हकदार हैं, जो वे अपने बच्चों को देती हैं। उन्होंने कहा, तो अब मैं खुद को कम आलोचनात्मक नजरिए से और ज्यादा दयालुता के साथ देखना सीख रही हूं। मैं खुद को ठीक होने, मजबूत महसूस करने और फिर से सहज महसूस करने के लिए समय दे रही हूं। जो भी मां ऐसा महसूस कर रही है, उसे बता दूं, आप अकेली नहीं हैं। हम भी उसी कोमलता की हकदार हैं, जो हम अपने बच्चों को देती हैं। 6 अप्रैल को करिश्मा और उनके पति वरुण बंगेरा ने घोषणा की थी कि वे पहली बार माता-पिता बनने जा रहे हैं।

बच्चों को भी बराबरी से मिले इंटरनेट सुविधा

करीब 25 साल पहले की बात है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बस्ती के पास, एक दीवार पर इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ कंप्यूटर लगाया गया था। वहां न कोई शिक्षक था, न मदद या मार्गदर्शन करने वाला और न ही किसी तरह के निर्देश दिए गए थे। आस-पास के बच्चे इस कंप्यूटर को देखने आए। उन्होंने कंप्यूटर के माउस से खेलना शुरू किया। खेलते हुए बच्चों ने आपस में सलाह-मशविरा भी किया होगा। खेलते-खेलते, देखते-देखते और कोशिश करते हुए वे अपने आप सीख गए कि इंटरनेट पर कैसे और कहां सफर किया जा सकता है।

कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अंग्रेजी में था और इंटरनेट पर मौजूद सामग्री भी अंग्रेजी में थी। बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ़ लिया। वैज्ञानिक डॉ. सुगाता मित्रा का यह प्रसिद्ध प्रयोग 'होल इन द वॉल' के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की खबर पढ़ी, जिसमें बच्चों के इंटरनेट की पहुंच को बच्चों के मौलिक अधिकारों से जोड़कर देखा गया है। यह खबर पढ़ते ही मुझे अनायास 'होल इन द वॉल' प्रयोग की याद हो आई।

आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, इंटरनेट के असीम संसार को खोजने, समझने और उसका उपयोग करने के लिए हमें अपने बच्चों को कुशलता और सावधानी के साथ तैयार करना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के सीखने, खोजने और अनुसंधान करने के तरीकों का विस्तार हो सकता है। उन्हें किसी विषय को और गहराई से समझने एवं अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर तलाशने के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि घर हो या स्कूल, या कोई दूर-दराज का इलाका- हर बच्चे को इंटरनेट तक पहुंचने का समान, सुलभ और सुरक्षित रास्ता मिले।

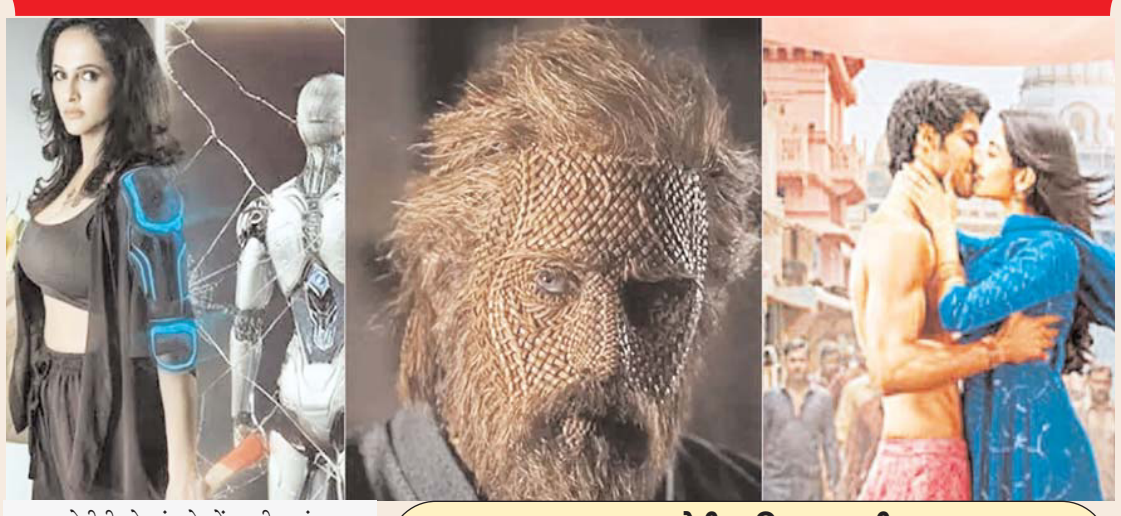
पिछले बीस वर्षों से देश के ग्रामीण जिलों में 'असर' सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं या नहीं और उनमें पढ़ने व गणित के सवाल हल करने की बुनियादी क्षमताएं कितनी विकसित हुई हैं। बच्चों और उनके परिवारों से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां भी इसमें जुटाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण भारत के 90 फीसदी परिवारों के पास साधारण मोबाइल फोन थे, जबकि केवल 36 फीसदी परिवारों के पास स्मार्टफोन। कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया। वर्ष 2022 में 74 प्रतिशत और 2024 में 84 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन पाए गए। 2024 के 'असर' सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 14 से 16 वर्ष की आयु के 82 प्रतिशत लड़के-लड़कियां न सिर्फ स्मार्टफोन के बारे में जानते थे, बल्कि उसका उपयोग करना भी समझ रहे थे। सर्वेक्षण के दौरान इन बच्चों को स्मार्टफोन पर कई काम करने के लिए दिए गए, जैसे कोई जानकारी खोजना, किसी खास विषय से जुड़ी सामग्री ढूंढ़ना और अपने परिचित किसी व्यक्ति को संदेश भेजना। लगभग 75 प्रतिशत बच्चे ऐसे काम आसानी से कर पाए। गौरतलब है कि इनमें से कई बच्चों के पढ़ने और गणित के बुनियादी कौशल अब भी कमजोर थे।



निस्संदेह, आज के दौर में इंटरनेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों और बच्चों की सुरक्षा की जरूरत को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) - दोनों दस्तावेज, शिक्षा में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ सावधानी, निगरानी और उचित दिशा-निर्देशों की जरूरतों पर जोर देते हैं। इसलिए बच्चों और उनके अभिभावकों, दोनों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, ताकि बच्चे इंटरनेट का सुरक्षित, जिम्मेदार एवं उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकें। 'असर' 2024 के सर्वेक्षण में 14-16 वर्ष के किशोरों से इंटरनेट सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे गए थे। उनसे पूछा गया कि क्या वे प्रोफाइल को रिपोर्ट करना जानते हैं, अपनी प्रोफाइल की निजता समझते हैं और अपना पासवर्ड बदलना जानते हैं? सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे बच्चे इन सबसे अनजान थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को लगातार सुरक्षा के मजबूत उपाय विकसित करने होंगे और उन्हें उनके लिए जवाबदेह भी ठहराना होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के नाम पर उन पर इंटरनेट या सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना उचित नहीं होगा। वैसे भी, अतीत के अनुभवों से समझा जा सकता है कि कानूनी प्रतिबंध लगा देने भर से किसी गतिविधि को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। जाहिर है, हमें डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट को बच्चों की शिक्षा और विकास का सुरक्षित, जिम्मेदार और समान अवसर देने वाला माध्यम बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। इसके लिए बच्चों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, उन्हें सही निर्णय लेने के लिए तैयार करना और अभिभावकों व शिक्षकों को भी आवश्यक जानकारी और कौशल देना बेहद जरूरी है। इंटरनेट से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे अपनी पसंद के विषयों के बारे में और गहराई से जान सकते हैं और अपने आस-पास की दुनिया से आगे बढ़कर पूरी दुनिया को समझ सकते हैं।

पिक्चर देखने जाने का बन रहा है प्लान? जानिए थिएटर्स में रिलीज होंगी कौन सी फिल्में



आज ओटीटी ने एंटरटेनमेंट की पहुंच बहुत व्यापक कर दी है। बेडरूम से लेकर ड्रॉइंग रूम तक और सफर करने से लेकर बाकी हर जगह तक मोबाइल और स्मार्ट टीवी के जरिए ओटीटी ने एंटरटेनमेंट पहुंचा दिया है। हालांकि आज भी थिएटर की अपनी धाक है। बड़े पर्दे पर जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी के साथ फिल्म देखने का आज भी अपना मजा है, जिसे अभी तक कोई दूसरा मीडियम रिप्लेस नहीं कर पाया है। यही वजह है कि आज भी भारत में सिनेमाघर जाकर पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने का चलन बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते थिएटर्स में कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो आपको परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का विकल्प बन सकती हैं। क्योंकि दिवाली करीब है और हर फिल्ममेकर अपनी फिल्म छुट्टियों के आसपास रिलीज करना चाहता है, ऐसे में इस हफ्ते दर्शकों के लिए कोई खास बड़ी फिल्म नहीं है। हालांकि जितनी फिल्में हैं, उनमें के अपनी पसंद के मुताबिक किसी अच्छे जॉनर की फिल्म देखने के लिए आप सिनेमाघरों का रुख कर सकते हैं।

लव स्टोरी अभिमन्यु की

खबरों की मानें तो इस फिल्म का नाम पहले 'यादव जी की लव स्टोरी' रखा गया था। जिसे बाद में बदलकर 'लव स्टोरी अभिमन्यु की' कर दिया गया। कहानी की बात करें तो यह एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पहले प्यार और अपने परिवार के दबाव में तय किए गए लड़के (अभिमन्यु यादव) के बीच फंसी हुई है।

देसीपन से हटकर अगर कुछ युनिक या हॉलीवुड स्टाइल देखना पसंद है तो आप 'विकर' देखने भी जा सकते हैं। यह फिल्म उर्सुला विल्स-जोन्स की शॉर्ट स्टोरी 'ञ्जद्धद्ग ह्लद्बह्लष्द्मद्गह्ल HusbandÓ पर आधारित है। कहानी एक ऐसी मछुआरी औरत की है जिसे समाज से अलग-थलग कर दिया गया है। वह अपने लिए एक 'विकर' (लकड़ी की तीलियों से बुना हुआ) पति मंगवाती है। इसके बाद पूरे रूढ़िवादी गांव में हंगामा मच जाता है।

30 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में आएगी किलर

यह फिल्म भी बाकियों की तरह 30 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में आएगी। यह एक स्काई-फाई थ्रिलर मूवी है। कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो अपने भीतर ढेरों रहस्य समेटे हुए है। आतंकवादी, जासूस, एक्ट्रेस, वैंपायर... आखिर वो क्या है? क्या वह एक ही लड़की है, या फिर एक ही चेहरे वाली कई लड़कियां हैं। उसको आखिर क्या हुआ था और उसका अतीत क्या है।

द कलकत्ता फाइल्स

सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह पॉलिटिकल ड्रामा मूवी उनके लिए है, जिन्हें द बंगाल फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में पसंद आई हैं। रजतवा दत्ता, स्वागत मुखर्जी, गौरव रॉय चौधरी और पायल दास स्टारर यह मूवी थिएटर्स में इसी इसी हफ्ते आएगी।

रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्मनखरेवाली

यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव ने लीड रोल प्ले किया है। मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को (वोमेंटिक कॉमेडी) कहा है। फिल्म का पोस्टर कहता है- 'कभी-कभी प्यार में मजनू को भी लैला बनना पड़ता है'। यह फिल्म आज के जमाने के रिश्तों, जेंडर रोल्स में बदलाव और सामाजिक सोच को हल्के-फुल्के अंदाज में बड़े पर्दे पर दिखाती है। यह मूवी थिएटर्स में 30 अक्टूबर को रिलीज होगी।

Bigg Boss 20 रोहित शेट्टी ने लगाई आम्रपाली की क्लास



बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में काफी हंगामा हुआ। वीकेंड का वार में तब सब हैरान हो गए जब स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी आईं। स्काउट को तो झटका लगा था। स्काउट और काश्वी के बीच काफी बातचीत हुई। लेकिन जब काश्वी जा रही होती हैं तब कुछ ऐसा होता है कि रोहित शेट्टी, आम्रपाली दुबे को डांट देते हैं। दरअसल, लास्ट वीकेंड का वार को रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था। रोहित पहले लव गिल और स्काउट के रिश्ते पर सवल खड़े करते हैं। इसके बाद वह काश्वी को लेकर आते हैं। काश्वी जब बात करके वहां से जा रही होती हैं तब आम्रपाली बोलती हैं कि यार काश्वी, हम तुम्हें मन ही मन भाभी बुलाने लगे थे।

कुछ ने आम्रपाली को सपोर्ट किया

लोगों ने सवाल उठाए कि आम्रपाली ने कुछ गलत नहीं कहा है क्योंकि स्काउट ने खुद काश्वी के बारे में सबको बताया है बिग बॉस में। स्काउट शो में अपने साथ काश्वी की फोटो भी लेकर आए हैं तो इसलिए आम्रपाली का ऐसा कहना गलत नहीं था।

खैर देखते हैं कि अब वीकेंड का वार के बाद स्काउट और लव गिल के बीच कैसा बॉन्ड रहता है। क्या दोनों अपनी क्लोज फ्रेंडशिफ को खत्म कर देंगे या आगे भी वैसा ही चलता रहेगा।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

रोहित शेट्टी बोले बेवकूफ लग रहे हो

आम्रपाली की इस बात पर रोहित शेट्टी नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत गुस्से में कहा बेवकूफ लग रहे हो आम्रपाली आप लोग, जो टीवी पर चल रहा है, ये सब बोलकर। आम्रपाली बोलती हैं कि आई एम सॉरी सर, मैं यहां जो हो रहा है उस पर बोल रही हूं। रोहित फिर बोलते हैं कि जो लड़की प्यार करती है, उसके साथ क्या चल रहा है, आप लोगों को पता है? कम्यूनिटी सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरे लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बाहर गर्लफ्रेंड है और अंदर ये सब हो रहा है।

कुछ ने किया रोहित को सपोर्ट

रोहित के इस स्टेटमेंट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोगों ने रोहित को सपोर्ट किया कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन कुछ को पसंद नहीं आया जिस तरह से उन्होंने आम्रपाली को जवाब दिया।



रामायण में भगवान राम बनने से पहले डर गए थे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले फिल्म का खूब जोर-शोर से प्रमोशन किया जा रहा है। अब फिल्म की टीम अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची। इस दौरान रणबीर कपूर ने भगवान राम के किरदार को करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रणबीर ने बताया कि वह पहले डरे हुए थे इस किरदार को करने के लिए। रणबीर ने कहा, 'सर जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, मैं जानता था कि ये सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मेरा जो पहला इंस्टिंक्ट था डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा क्योंकि प्रभु राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है।' एक्टर ने फिर कहा, 'लेकिन फिर जो डर था वो आभार में बदला। मुझे इस मुकाम में, इस उम्र में ये रोल ऑफर हुआ। मुझे एक बेहतर एक्टर, एक्टर छोड़िए सर, एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला।'रणबीर ने आगे कहा, 'उसी दौरान मैं पहली बार पिता बना। मेरी बेटी राहा का जन्म हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये भगवान का तोहफा है मुझे रामायण का हिस्सा बनने का मौका मिला। बेहतर इंसान बनने का मौका मिला।' इसी दौरान रवि दुबे से बिग बी ने लक्ष्मण का किरदार निभाने का एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं। अब भी मुझे ये बिलीव नहीं हुआ है। मैं और मेरी पत्नी सरगुन मानते हैं कि चीजें जो होती हैं तो वो डिवाइन से होती हैं। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर-राम, साई पल्लवी-सीता, रवि दुबे-लक्ष्मण, यश-रावण, सनी देओल-हनुमान का किरदार निभा रहे हैं।

अध्यात्मिक रंग में रंगे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली,



बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर अपनी सादगी और आध्यात्मिक लगाव को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में दोनों मुंबई में अमेरिकी गायक कृष्णा दास के लाइव कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान कपल भक्ति के रंग में डूबा नजर आया। अब इस कार्यक्रम से अनुष्का और विराट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों बड़े ध्यान से कृष्णा दास का कीर्तन सुनते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरि नाम जपते हुए कपल भक्ति संगीत की धुन पर हल्के-हल्के झूमता भी नजर आया। वीडियो में दोनों काफी शांत और खुश दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में अनुष्का और विराट कुछ सेकंड के लिए कैमरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना ध्यान कीर्तन की ओर लगा लेते हैं। दोनों का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं।

कौन हैं कृष्णा दास?

बता दें कि कृष्णा दास अमेरिका के मशहूर भक्ति गायक हैं। वह भारतीय भजन और मंत्रों को पश्चिमी संगीत के साथ मिलाकर गाने के लिए जाने जाते हैं। दुनियाभर में उनके कीर्तन को काफी पसंद किया जाता है। मुंबई में हुआ यह कार्यक्रम उनके भारत दौरे का हिस्सा था, जिसमें अनुष्का और विराट भी शामिल हुए। बता दें कि कीर्तन में शामिल होने से पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी नजर आए थे। इस दौरान दोनों का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला।

क्या राजनीति में कदम रखेंगे धनुष? पहली बैठक के बाद बढ़ी हलचल

दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर सिनेमा और सत्ता के बीच की दूरी कम होती दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एक और बड़े अभिनेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यह नाम है तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता धनुष का है। उन्होंने अपनी अदाकारी से तमिल सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक पहचान बनाई। अब हाल ही में धनुष की चेन्नई के बाहरी इलाके सेम्मनजेरी में फैंस क्लब महिला विंग से मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि धनुष तमिलनाडु में 2031 में होने वाले चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु की सड़कों पर उनके पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यह चर्चाएं भी हो रही है कि धनुष जल्द ही किसी पार्टी के साथ भी जुड़ सकते हैं। हालांकि, अगर ऐसा होता भी है, तो धनुष कोई ऐसे पहले सितारे नहीं हैं, जो राजनीति में आ सकते हैं। इससे पहले भी कई साउथ स्टार रहे हैं, जो अभिनेता से राजनेता बन चुके हैं।



'जेलर 2' के आगे 'उड़ता तीर' की रफ्तार हुई धीमी,

'नई-नवेली' पर भारी 'प्रहार', जानें कमाई

सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'जेलर 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है। यह 400 करोड़ क्लब में एंट्री लेने से सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। इसके अलावा सिनेमाघरों में कॉमेडी स्पाई फिल्म 'उड़ता तीर' लगी है। वहीं, यामी की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार' पहले से लगी हैं। जानिए इनकी रविवार की कमाई कितनी रही?

जेलर 2 का बॉक्स ऑफिस कितना?

फिल्म 'जेलर 2' रिलीज के बाद से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वीकएंड पर इस शानदार कमाई में और भी इजाफा हो गया है। कल शनिवार को इस फिल्म ने 24.15 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, आज रविवार को 11वें दिन खबर लिखे जाने तक प्राप्त आंकड़ों में कलेक्शन 19.56 करोड़ रुपये हो गया है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 392.56 करोड़ रुपये हो चला है।

'उड़ता तीर' की रफ्तार कितनी बढ़ी?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुस्त ओपनिंग ली थी। मगर, वीकएंड पर हालत थोड़ी ठीक हुई है। कल शनिवार को कमाई 7.25 करोड़ रुपये थी। वहीं, आज रविवार को तीसरे दिन का कलेक्शन 5.93 करोड़ रुपये हो गया है। अंतिम परिणाम आने तक कमाई में इजाफा होगा। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 17.28 करोड़ रुपये हो चुका है।

'नई नवेली' और 'प्रहार' का कलेक्शन

यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' और राजकुमार राव अभिनीत 'प्रहार' एक ही दिन रिलीज हुई थी। शुरुआत में 'नई नवेली' ने अच्छा प्रदर्शन किया। मगर, वक्त बीतने के साथ प्रहार ने बढ़त बना ली है। कल शनिवार को नई नवेली ने 95 लाख रुपये कमाए थे। वहीं, आज रविवार को कमाई 82 लाख रुपये है। यामी की फिल्म का टोटल कलेक्शन 24.52 करोड़ रुपये है। वहीं, 'प्रहार' ने कल शनिवार को नौवें दिन 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे। आज रविवार को 10वें दिन का कलेक्शन 1.02 करोड़ रुपये है। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 19.92 करोड़ रुपये हो गया है।

सिंगापुर के कस्टम्स चीफ पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार



सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का क्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म के गाने 'हुकुम रीलोडेड' पर लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब सिंगापुर कस्टम्स चीफ भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ रजनीकांत के अंदाज में फिल्मी एंट्री की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

वायरल हुआ सिंगापुर कस्टम्स के चीफ का वीडियो

सिंगापुर कस्टम्स के चीफ के वीडियो में देखने को मिला कि वह जेल की कोठरियों के बीच से गुजरते हुए रजनीकांत के अंदाज में एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में 'जेलर 2' का गाना 'हुकुम रीलोडेड' बज रहा है। कुछ देर बाद उनके साथी अधिकारी भी इस फिल्मी एंट्री में शामिल हो जाते हैं। वीडियो के आखिर में एक दिलचस्प मैसेज भी दिया गया है, जिसमें लिखा है कि एंट्री भले



रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का गाना 'हुकुम रीलोडेड' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने को मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। यह साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'जेलर' के लोकप्रिय गाने 'हुकुम- थलाइवर अलप्पारा' का नया वर्जन है। नए गाने में पुराने गाने की दमदार धुन और रजनीकांत के खास अंदाज को बरकरार रखा गया है। इसमें वही म्यूजिक और बिगुल जैसी आवाज सुनाई देती है, जो रजनीकांत की स्क्रीन पर एंट्री को और दमदार बनाती है। इस गाने पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार डांस और एंट्री वीडियो बना रहे हैं। इसी बीच रजनीकांत ने भी अपने फैंस को खास सरप्राइज दिया। शुक्रवार रात वह चेन्नई के एक मल्टीप्लेक्स में आम दर्शकों के बीच अपनी फिल्म 'जेलर 2' देखने पहुंचे। खास बात यह है कि करीब 40 साल बाद रजनीकांत अपनी किसी फिल्म को देखने के लिए इस तरह पब्लिक थिएटर में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनके नाती लिंगा और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर भी मौजूद थे। रजनीकांत चेन्नई के वेलाचेरी स्थित फीनिक्स मार्केट सिटी के पीवीआर सिनेमाज पहुंचे थे।

परिणीति चोपड़ा की सीरीज से हटाए गए अनुप सोनी के एक्शन सीन

अभिनेता अनूप सोनी हाल ही में नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' में नजर आए थे। इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा और जेनिफर विंगेट भी अहम भूमिकाओं में थीं। शो में इंस्पेक्टर खुराना का किरदार निभाने वाले अनूप सोनी ने अब अपने कुछ सीन डिलीट किए जाने पर निराशा जाहिर की है। शनिवार को एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने डिलीट हुए सीन के वीडियो शेयर किए और बताया कि ऐसे सीक्वेंस तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कई बार इन्हें फाइनल कट में जगह नहीं मिल पाती।अनूप सोनी ने इंस्टाग्राम पर सीरीज से हटाए गए कुछ एक्शन सीक्वेंस की झलक दिखाई है। एक वीडियो में घायल अनूप सोनी पर उनके को-स्टार विक्की अरोड़ा हमला करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक सीन में अनूप उनका गला दबाते दिखाई देते हैं। वहीं, दूसरे वीडियो में एक्टर की कमर पर कैमरा बंधा हुआ है और वह हांफते हुए नजर आ रहे हैं। इन सीन्स को शूट करने के लिए एक्टर ने काफी मेहनत की थी, लेकिन इन्हें सीरीज के फाइनल वर्जन में शामिल नहीं किया गया। इन वीडियो को शेयर करते हुए अनूप सोनी ने लिखा, 'शक से खुराना साहब के कुछ ऐसे सीक्वेंस, जो फाइनल वर्जन का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे सीक्वेंस तैयार करने में काफी सोच-विचार, समय, मेहनत और संसाधन लगते हैं। इसमें राइटर्स, डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर, एक्टर्स, सिनेमैटोग्राफर, प्रोड्यूसर और पूरी क्रू टीम का योगदान होता है।हालांकि, अनूप सोनी ने यह भी माना कि फिल्म मेकिंग में इस तरह के फैसले लेना आम बात है।



बिहार में धार्मिक पर्यटन से बदलेगी तस्वीर!

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया विकसित बिहार का ऐसा रास्ता, जिससे खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

सुहैल खान





कैमूर(संवाददाता)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत परसिया गांव में आयोजित श्री भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्य सहस्राब्दी महामहोत्सव एवं दिव्य-भव्य विराट अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे साधु-संतों, धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया तथा मां मुंडेश्वरी की पावन धरती को नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति, संत समाज के मार्गदर्शन और जनसहभागिता को विकसित भारत तथा समृद्ध बिहार के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने धार्मिक विरासत के संरक्षण, मंदिरों के विकास, पर्यटन के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं ने हजारों वर्षों से दुनिया को दिशा देने का काम किया है। सनातन धर्म का दर्शन, उसकी मान्यताएं और जीवन मूल्य भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने में संतों तथा धर्माचार्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के आशीर्वाद, सनातन संस्कृति की शक्ति और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत तथा समृद्ध बिहार का सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक आयोजनों को भारतीय परंपराओं, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करने का माध्यम बताया। परसिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और धर्माचार्यों की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में अनेक ऐसे प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जिनका आध्यात्मिक महत्व देशभर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष है। इन स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और बेहतर सुविधाओं के विकास से धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने गयाजी के विष्णुपद मंदिर, सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर और कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर का उल्लेख करते हुए धार्मिक स्थलों के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना का उल्लेख किया। इसी तरह सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की बात भी कही। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की महत्ता के अनुरूप उनके विकास और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बिहार की धार्मिक विरासत राज्य की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन मंदिरों और तीर्थस्थलों का संरक्षण केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिहाज से भी आवश्यक है। ऐसे स्थलों के व्यवस्थित विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

कैमूर जिले में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने मां मुंडेश्वरी धाम और गुप्तधाम के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैमूर की धार्मिक पहचान और प्राकृतिक विशेषताएं इसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। यहां के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने और उनकी पहचान व्यापक स्तर पर स्थापित करने से अधिक श्रद्धालु तथा पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं। मां मुंडेश्वरी धाम कैमूर की प्रमुख धार्मिक पहचान में शामिल है। वहीं, गुप्तधाम भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इन स्थानों के विकास के साथ पर्यटकों की सुविधा, क्षेत्रीय संपर्क और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान देने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कैमूर की पहाड़ियों और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए पर्यावरण आधारित पर्यटन यानी इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। धार्मिक पर्यटन के साथ प्राकृतिक पर्यटन को विकसित करने से जिले की विशेषताओं को व्यापक पहचान मिल सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवाओं और व्यवसायों के विस्तार की संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में रोजगार सृजन को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य के भीतर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार की तलाश में मजबूरी के कारण दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए बिहार में ही काम के अवसर बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उद्योगों की स्थापना, निवेश को प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने क्षेत्र में काम मिल सके। उन्होंने बिहार से बाहर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले लोगों से भी अपील की कि वे अपनी जन्मभूमि के विकास में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में यहां के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राज्य के बाहर अनुभव और उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग भी अपने प्रदेश की प्रगति में सहयोग देकर विकास की प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास से बिहार में विकास की गति को मजबूती मिली है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं उद्योगों, पर्यटन और स्थानीय कारोबार के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करती हैं। उन्होंने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन के प्रयासों को आवश्यक बताया। धार्मिक पर्यटन और इको टूरिज्म के विस्तार को भी उन्होंने स्थानीय रोजगार की संभावनाओं से जोड़ा। पर्यटन स्थलों पर गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर सेवाओं और कारोबार को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे क्षेत्र के लोगों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि धार्मिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिल सके।

नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त मां–बेटी गिरफ्तार

बक्सर (संवाददाता)।



बक्सर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों पर हेरोइन जैसी नशीली पदार्थ की पुड़िया और विदेशी शराब घर में छिपाकर बेचने का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 30 पुड़िया में रखे कुल 11.6 ग्राम मादक पदार्थ और एक लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शांति नगर निवासी सोना देवी (45 वर्ष) और रानी राजभर (19 वर्ष) के रूप में हुई है।

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में सोना देवी अपनी बेटी रानी के सहयोग से बाहर से हेरोइन और शराब लाकर घर में बालू के अंदर छिपाकर बेचने का काम कर रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने संबंधित स्थान पर छापेमारी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 30 पुड़िया में रखा 11.6 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ तथा एक लीटर विदेशी शराब बरामद की। बरामदगी के बाद नगर थाना में कांड संख्या 559/26, दिनांक 25 अक्टूबर 2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने संबंधित मामले में NDPS एक्ट की धारा 8(a)(c)/21(c) तथा बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(a) के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय, नगर थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक मुन्ना कुमार यादव, पुलिस अवर निरीक्षक अनिशा भारती तथा नगर थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे। पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में मादक पदार्थ और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जनसुनवाई में पहुंचे 30 आवेदन, राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक

बक्सर (संवाददाता)। आम जनता की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर समाहर्ता बक्सर अरुण कुमार सिंह एवं अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शशिकांत पासवान ने संयुक्त रूप से विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर पहुंचे तथा अधिकारियों के समक्ष कुल 30 आवेदन प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों में सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे। कुल 30 आवेदनों में 12 आवेदन राजस्व विभाग, 9 आवेदन विकास से संबंधित तथा 9 आवेदन अन्य संबंधित विभागों से जुड़े थे। विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष विस्तार से रखा और उनके समाधान की मांग की। अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक की बात को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। अधिकारियों ने संबंधित विभागों से जुड़े मामलों की जानकारी लेते हुए मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए। जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों ने आम लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। सभी आवेदनों का निष्पादन पारदर्शी, न्यायोचित एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है। जिला प्रशासन जनसहभागिता और जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तथा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है।

डीएम साहिला ने बढ़ाया हौसला

एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती टीम को सहयोग देने वाले बक्सर के पहलवान अविनाश कुमार सम्मानित

बक्सर (संवाददाता)।



कुश्ती के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले बक्सर के पहलवान अविनाश कुमार को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी साहिला ने अविनाश कुमार को सम्मानित करते हुए जापान में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में कुश्ती टीम को सहयोग प्रदान करने में उनके योगदान की सराहना की। जिला प्रशासन की ओर से मिले इस सम्मान से खेल जगत से जुड़े लोगों और युवाओं में उत्साह का माहौल है।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी साहिला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की सफलता केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कठिन परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और सामूहिक प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी टीम को मिलने वाला सहयोग और खिलाड़ियों के बीच बेहतर समन्वय सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। डीएम ने कहा कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ टीम के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग, सकारात्मक सोच और टीम भावना भी बेहतर परिणाम हासिल करने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में अविनाश कुमार द्वारा कुश्ती टीम को सहयोग प्रदान करना उनके खेल के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान देना जरूरी है। ऐसे सम्मान से खिलाड़ियों और खेल से जुड़े युवाओं का मनोबल बढ़ता है तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन बक्सर जिले की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं में खेल के प्रति रुचि विकसित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने अविनाश कुमार के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही उम्मीद जताई कि वे भविष्य में भी खेल जगत से जुड़े रहकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और बक्सर जिले का गौरव बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

दिल्ली की रैली के लिए बक्सर कांग्रेस ने तेज की तैयारी, 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचेंगे कार्यकर्ता

बक्सर (संवाददाता)। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी 1 नवंबर 2026 को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली को सफल बनाने के लिए बक्सर जिला कांग्रेस कमिटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को गोलंबर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। जिला कांग्रेस कमिटी के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बक्सर प्रभारी विश्वारंजन मोहन्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों, बक्सर जिले से नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी तथा दिल्ली प्रस्थान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और संगठन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय मजबूत बनाने पर जोर दिया।



प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बक्सर प्रभारी विश्वारंजन मोहन्ति ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं और इसमें जनता का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। मतदाताओं को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का अवसर मिले तथा चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर किसी प्रकार की शंका न रहे, यह लोकतंत्र के हित में जरूरी है। विश्वारंजन मोहन्ति ने कहा कि प्रस्तावित रैली के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे कथित 'वोट चोरी' जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना कांग्रेस की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने का आह्वान किया।

जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली को सफल बनाने के लिए बक्सर जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंकज उपाध्याय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर दिल्ली पहुंचने और लोकतंत्र एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी किसी भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर रैली की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान विश्वारंजन मोहन्ति ने पार्टी संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और आगामी कार्यक्रम को लेकर आवश्यक विचार-विमर्श किया। नेताओं ने रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा दिल्ली प्रस्थान की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिले के विभिन्न प्रखंडों से कार्यकर्ताओं को किस तरह कार्यक्रम से जोड़ा जाए और संगठनात्मक स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने रैली की तैयारियों को व्यवस्थित करने और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के प्रति सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे, उमाशंकर पांडे, राजारमन पांडे, जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, प्रखंड अध्यक्ष राजा तिवारी, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला देवी सहित जिला कांग्रेस कमिटी के पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने मीडिया प्रतिनिधियों को आगामी रैली की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से अवगत कराया। बैठक में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन की सक्रियता बढ़ाने तथा दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम में जिले की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480